मासिक समाचार पत्र

सीमित प्रसार के लिये

लोकविद्या पंचायत

● सूचना युग में बराबरी के विचार के पुनर्निर्माण का पत्र ●
● लोकविद्याधर समाज के पुनर्संगठन का वैचारिक आधार पत्र ●
● पूँजी आधारित समाज के स्थान पर ज्ञान आधारित समाज के निर्माण का विचार पत्र। ●

अंक 2, पृष्ठ : 8 | मई 2010 | सहयोग राशि : 5 रुपये

किसान संगठनों का दिल्ली में धरना-प्रदर्शन

विगत नौ मार्च को भारतीय किसान यूनियन ने गेहूँ और धान के दाम को मुख्य मुद्दा बनाकर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का धरना-प्रदर्शन आयोजित किया। जंतर-मंतर पर इस धरने का किसानों के मसीहा चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत ने खुद नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुल पचास हजार के लगभग किसान इस धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए।

किसानों ने धरना प्रदर्शन में जो माँग पत्र बनाया उसके प्रमुख मुद्दों में देश के बजट को कारपोरेट समर्थक तथा किसान विरोधी करार देते हुए किसान हित का बजट प्रस्तुत करने की बात कही। न्यूनतम समर्थन मूल्य में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाय। अनुदान का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता अतः किसानों को सीधे अनुदान की सुविधा प्रदान की जाय। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाय। किसानों के लिए 4% की दर पर कर्ज की सुविधा प्रदान की जाय। प्राकृतिक आपदा से निजात पाने के लिए किसानों के लिए फसल बीमा योजना चलायी जाय। कृषि में विश्व व्यापार पर भारत में प्रतिबंध लगाया जाय।

भा०कि०यू० उत्तर प्रदेश के महासचिव राजेन्द्र शास्त्री ने अपनी बात में कहा कि मंदी के दौर में भी भारत की स्थिति संभली रही इसका श्रेय किसानों को जाता है। इस किसानी की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था मुफ्त हो और खाद, बीज समय से मिले। 5 हार्स पावर की बिजली शुल्क मुक्त होनी चाहिए। वर्तमान में गेहूँ का समर्थन मूल्य 1500/- रूपये प्रति कुन्तल किया जाय। आलू के दाम में व्याप्त असन्तुलन को दूर किया जाय तथा तिलहन व दलहन के खरीद की व्यवस्था भी समर्थन मूल्य के आधार पर हो।

भा०कि०यू० उत्तराखण्ड के अध्यक्ष, चौधरी राम सिंह पवार ने कहा कि सरकार ने बयान दिया है कि गेहूँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इसका परिणाम यह निकलना तय है कि समर्थन मूल्य रूपये 1100/- की जगह पूँजीपति 7-8 सौ में खरीदने की मार करेंगे। जहाँ गेहूँ पैदा होता है वहाँ पर सरकार का गोडाउन भरा हुआ है और जहाँ गोडाउन नहीं भरा है --

भा०कि०यू० उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बिना भेद-भाव किये समस्त किसानों के लिए पेंशन देने की योजना शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग

चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत

थोड़े दिन नौकरी करने के बाद जीवन भर पेंशन लेते हैं और किसान जीवन भर खेती का कार्य सम्पादित करने के बाद भी पेंशन नहीं पाता। किसान का यह अधिकार है कि उसे पेंशन मिले।

कर्नाटक रैयत संघ के अध्यक्ष चन्द्रशेखर ने कहा कि हम कर्नाटक से 2500 किमी. चलकर आये हैं। देश में करीब 2,50,000 लोग आत्महत्या कर चुके हैं लेकिन पार्लियामेन्ट के लोगों को इसकी चिन्ता नहीं है। पिछले चुनाव के समय कांग्रेस ने किसानों और मजदूरों के चौसठ हजार करोड़ रूपये कर्ज को माफ करने की बात की लेकिन इस समय वह लागू नही हो रहा है। पार्लियामेन्ट के लोगों को देहात के लोगों से हमदर्दी नहीं है, ये बाहर से फूड मँगवा रहे हैं, चीनी मंगवा रहे है। पिछले कुछ समय से खाने का तेल दूसरे मुल्क से मंगवा रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि तिलहन का दाम गिर गया। यहाँ के किसान का हाल क्या होगा इस पर प्रश्न करना है। बीज उत्पादन के अधिकार का कानून बदल कर ये कंपनियों को देने जा रहे हैं। कंपनी हमें लूटेंगी। इन्हें क्या सोचना है? किसान को सोचना होगा। नगरीकरण के लिए, सेज के लिए, कल-कारखाने वालों को देने के लिए किसानों की जमीन हड़प कर ली जा रही है। हम मनमोहन सिंह, सोनिया को चेतावनी दे रहे हैं कि खेत को दूसरे काम में लगाया गया तो अनाज उत्पादन न होने पर देश का क्या होगा। कर्नाटक सरकार नाइस कम्पनी को 23,000 एकड़ जमीन देने जा रही है। आज इसे रद्द करने के लिए हम धरना दे रहे हैं। चौ. महेन्द्र सिंह टिकैत से निवेदन है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में न बैठें पूरे देश के किसानों के हित में किसान विरोधी सरकार को हटाया जाय।

... शेष पेज 2 पर

बिजली ने काटे बुनकरों के हाथ

बुनकर समाज में बिजली की समस्या को लेकर बुनकर वेल फेयर संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक, हाजी रहमतुल्लाह अंसारी से संतोष कुमार संविज्ञ ने बातचीत की जिसमें अन्सारी साहब ने कहा कि – बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्धि के साथ जुड़ा है बुनकर समाज का ज्ञान, हुनर, और अदभुत कला। बुनकर समाज अपने ज्ञान का इस्तेमाल उपयुक्त संसाधनों की उपलब्धता से हीं कर पाता है। साड़ी बनानें के लिए कई प्रकार की तकनीकी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। बारीकी से कढ़ाई करनी पड़ती है। इसके लिए भरपूर रोशनी चाहिए। बुनकर समाज को समय से बिजली नहीं मिलती, काम के समय बिजली नहीं मिलती, इसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लोग बेकार बैठे रहतें हैं। सरकार की बुनकर विरोधी नीतियों के कारण हथकरघा तथा पावरलूम दोनों समाप्ति की ओर है। 1978-79 में केन्द्र व राज्य सरकारें यूपिका हैण्डलूम के माध्यम से बुनकरों की साड़ी खरीदती थी जिससे, छोटे-छोटे बुनकरों को भी लाभ मिलता था। उनकी पॉकेट में भी दो चार सौ रूपये बराबर रहता था। उनकी साड़ी खरीदने के लिए सरकार ने बुनकरों के लिए कार्ड बनवाया था। 1992 में सरकार ने यूपिका हैण्डलूम बन्द कर दिया तथा बुनकरों को मिलने वाली सुविधायें भी बन्द कर दी गयीं। तभी से बुनकर समाज की स्थिति बिगड़ती गई। उनका आर्थिक ढाँचा टूट गया। बुनकर समाज अपना खून बेचने, आत्महत्याएँ करने, तथा अपनी औलादों को बेचने के लिए विवश हो गये, कमाई घट गयी और ऊपर से बिजली का बिल बढ़ता गया।

प्र0- बुनकर समाज में बिजली की क्या-क्या समस्यायें है?

उ0- बुनकर समाज की सबसे बड़ी समस्या बिजली की समस्या है। 1992 से ही लगातार बुनकरी का धन्धा कमजोर होने से बुनकर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पायें, जिससे उनका 5-10 हजार रूपये का बकाया बिल बढ़ते-बढ़ते लाखों रूपये तक हो गया है। कम पैसा होने से बिजली विभाग कर्मचारी कुछ 400-500 रूपये लेकर बिजली जलाने की छूट देते थे। अधिक होने पर अब कनेक्शन काट रहे हैं। कर्मचारियों के उत्पीड़न से बचने के लिए वे जो पैसे देते थें उन पैसों से बुनकरों का न तो बिल कम हुआ और न ही राजस्व में वृद्धि हुई। पैसा पूर्णरूप से कर्मचारी घोट गयें।10-15 वर्ष पहले पावरलूम के लिए मीटर लगाया गया। धन्धा समाप्त हो गया है, लेकिन मीटर आज भी लगा है। मीटर चले न चले, बिजली रहे न रहे, लेकिन उसका पैसा देना है। नही देंगे तो आर0 सी0 कटेगा और जेल जायेंगे। बिजली बिल के कारण बुनकरों का पलायन भी हो रहा है। लोग सस्ते दर में मकान बेच रहे हैं। मकान खरीदने वाला बिजली बकाया को साथ जोड़कर मकान की कीमत तय करता है । दो लाख रूपये बिजली बकाया है तो 2 लाख घटा कर देता है जबकि मकान लेने के बाद 40-50 हजार रूपये में ही कर्मचारी से बिजली बकाया का हिसाब करा लेता है। यदि पूर्वांचल के बिजली विभाग के कर्मचारी की सम्पत्ति की जाँच हो जाय तो इतना अधिक पैसा जनता का कर्मचारियों ने लूटा है उसका खुलासा हो जायेगा। और उस पैसे से पूर्वांचल के बुनकर ही नही बल्कि किसान, दलित, गरीब हर व्यक्ति की समस्यायें हल हो जायेंगी।

प्र0- बुनकर समाज के बिजली के सवाल को लेकर आपकी समिति क्या कर रही है?

... शेष पेज 2 पर

भारतीय किसान यूनियन के प्रधानमंत्री को पत्र के मुख्य मुद्दे

20 मार्च को विभिन्न अधोहस्ताक्षरित किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री, भारत सरकार को एक पत्र लिखकर किसानों की दशा व संप्रग सरकार की कृषि के प्रति नीतियों के किसान विरोधी रूख को रेखांकित करते हुये निम्नलिखित बातें कहीं-

1) भारत सरकार का 2010-11 का बजट किसान विरोधी है और बड़ी पूँजीपति कम्पनियों के फायदे का है। उदाहरण के लिये प्रसंस्करण के लिये आवंटित बेशुमार निधि का कोई फायदा किसानों को नही होगा, सारा फायदा पूँजीपतियों और निगमों की जेब में जायेगा।
2) स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम मूल्य तय किये जाने चाहिये।
3) किसानों की आय वृद्धि को सीधा समर्थन दिया जाना चाहिये। छोटे व सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों में मजदूर परिवार मुश्किल से औसत 500 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कमा पाते हैं। इन परिवारों को जीवन यापन के बढ़ते खर्च से मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा सीधे आय-समर्थन दिया जाना चाहिये।
4) सभी को खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई जानी चाहिये जिसके अंतर्गत सभी आते हैं।
5) भविष्य के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाय, जिससे मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण किया जा सके। निगम थोड़ा सा ज्यादा दाम देकर कृषि उत्पाद पर पहले ही कब्जा कर लेते हैं। इससे अनाज की सरकारी आमद पर असर पड़ता है और जिसके चलते दाम बढ़ते हैं।
6) किसान की जमीन की मालियत के आधार पर खाद सब्सिडी दी जानी चाहिये।
7) किसानों के लिये कर्ज की सुविधा बढ़ाई जाय। 2008 में 70,000 करोड़ रूपये की कर्ज माफी के बावजूद उस वर्ष 16,196 किसानों ने आत्महत्या की। जाहिर है कि कर्ज माफी का लाभ उन किसानों तक नहीं पहुँचा। कर्ज नीति में तुरंत बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है।
8) खेती के सभी कर्जों पर 4% ब्याज लिया जाय। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है कि 4% यह ब्याज की अधिकतम सीमा होनी चाहिये।
9) प्राकृतिक आपदा के वक्त किसानों को सही मुआवजा मिले इसके लिये फसल बीमा लागू किया जाय।
10) विकास परियोजनाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिये किसानों की जमीनों का अधिग्रहण बंद हो।
11) कृषि विज्ञान केन्द्रों को मजबूत किया जाय जिससे किसान बीज और कीटनाशक कम्पनियों के नुमाइन्दों पर निर्भर न रहे।
12) जैव संशोधित बीज, फसल व खाद्य पदार्थ के शोध, उत्पादन और आयात सभी पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
13) कृषि को विश्व व्यापार संगठन के बाहर रखा जाय तथा कृषि के बाजार को मुक्त व्यापार समझौते के लिये खोला न जाये।

चौ० महेन्द्र सिंह टिकैत, अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन
अजमेर सिंह लखोवाल, अध्यक्ष, भा०कि०यू०, पंजाब
गुरनाम सिंह, अध्यक्ष, भा०कि०यू०, हरियाणा
पूरनमल सूँडा, भा०कि०यू०, राजस्थान
एस.एस. चीमा, भा०कि०यू०, उत्तराखण्ड

(युद्धवीर सिंह, प्रवक्ता किसान आंदोलन की भारतीय समन्वय समिति)

पेज 1 का शेष

किसान संगठनों ...

भा०कि०यू० हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में बल है। कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के अनुसार जनवरी 2006 से बढ़ी हुई तनख्वाह दे दी गई। स्वामीनाथन के रिपोर्ट के अनुसार मंहगाई को देखते हुए मूल्य तय करने होंगे। गेहूँ का रेट पिछले साल 1540/- था। उसे पूरा जोड़ने पर 2250/- रूपये होगा। 3% कर्मचारियों की बात मान ली गयी। किसानों को भी 2006 से बढ़े हुए रेट मिलना चाहिए। किसान सरकार का सभी कर्जा आज उतार देगा यदि सन् 2006 से जोड़कर पूरा बकाया मिल जाय।

भा0कि0यू0 बिहार प्रान्त के अध्यक्ष रामानुज ने 18 मई 2010 को पटना में राष्ट्रीय पंचायत होने की जानकारी दी और दिल्ली पधारे समस्त किसान भाइयों का आवाह्न किया कि किसान हित के लिए बिहार में शक्ति प्रदर्शन हेतु अवश्य आयें ताकि किसान दाम, बिजली, पानी, अधिग्रहण की समस्या से निजात पा सकें।

भा०कि०यू० मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जगदीश सिंह ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिजली के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार तीन लाख किसानों को जेल में ठूँस चुकी है।

भा०कि०यू० पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लोंगोवाल ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग बनाया और स्वामीनाथन ने सन् 2006 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। रिपोर्ट किसानों के हित से जुड़ी है। किसानों के उपज का जायज दाम मिले, जमीनों का धड़ल्ले से हो रहा अधिग्रहण रूके तथा बिजली, पानी की व्यवस्था ठीक हो। सरकार को ये बातें रास नहीं आयी, आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लटकाये रखा गया है। किसान सभी सुविधाओं का हकदार है। वृद्धावस्था काटने के लिए किसान पेंशन योजना हर हाल में लागू होनी चाहिए।

दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी युद्धवीर सिंह ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गन्ना की ही तरह गेहूँ, धान इत्यादि फसलों का दाम लेकर दम लिया जायेगा। हरियाणा के विजय पाल सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार किसानों को 17,000 करोड़ रूपये देने की बात करती रही, वह पैसा कहाँ गया?सरकार जो भी कानून बनाती है वह देश के 80% जनता के लिए क्यों नहीं बनाती। आज दिल्ली में हम भारी संख्या में आये हैं, सरकार को हमारी ताकत का एहसास हो जायेगा। हिन्दुस्तान का किसान अपना हक, अधिकार माँगने आता है तो उसे मेला बताया जाता है। सरकार के पास गोदाम नहीं है। सरकार चाहे तो हमें पैसा दे दे और उसे जब जरूरत पड़े हमसे गेहूँ ले लिया करे। गोदाम की कोई जरूरत नहीं है। सरकार हमारे पानी की व्यवस्था कर दे, किसान सबको खाना खिला देगा, पानी चाहिए तो सिर्फ सोनिया गाँधी को, राहुल गाँधी को। धरती माँ अपनी माँ है उसका अपमान नहीं होने देंगे। तीन साल पहले विदेश से 1600 रूपये कुन्तल गेहूँ खरीदा गया था, किन्तु हम किसानों को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है।

अन्त में चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत ने कहा कि हम दाम की लड़ाई लड़ने के लिए आये हैं। जब तक सरकार का कोई नुमाइन्दा नहीं आ जाता और उससे वार्ता नहीं हो जाती, तब तक हम सभी लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे, हम हटने वाले नहीं है। तमिलनाडु, कर्नाटक सहित हर जगह से लोग आये हुए हैं। रोज-रोज कोई नहीं आता अतः हमें पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहकर अपनी शक्ति का एहसास कराना होगा।

शाम के समय प्रशासन ने शासन के साथ वार्त्ता की व्यवस्था की। चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत, चन्द्रशेखरन व अन्य किसान नेताओं की प्रमुख सचिव, भारत सरकार के साथ वार्त्ता हुई। भा०कि०यू० के माँगपत्र पर विचार करके उनका समाधान करने के लिए एक कमेटी गठित की गयी जिसमें भा०कि०यू० के प्रतिनिधि को रखा गया। यह कमेटी माँग पत्र पर विचार करने के लिए कोई तिथि निर्धारित करके मीटिंग आयोजित कर समस्याओं का समाधान निकालेगी।

उपर्युक्त वार्ता के बाद दिल्ली का धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की गयी।

लक्ष्मण प्रसाद मौर्य
जिला अध्यक्ष, भा. कि. यू. , वाराणसी

पेज 1 का शेष

बिजली ने काटे...

उ0- केन्द्र व राज्य सरकार से 1992 से ही बुनकरों का बिजली बकाया माफ करने की माँग की जा रही है। सरकार में बैठे नेताओं से अनेक बार समिति के लोगों ने वार्ता की है, पत्रक दिया गया। बार-बार इन प्रक्रियाओं की निरन्तरता के कारण केन्द्र व राज्य सरकार का आदेश विद्युत विभाग को हुआ कि बुनकरों की सूची बनायी जाय जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बिजली का बकाया कितना है। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कभी भी सर्वे के कार्य पर पहल नही हुई। बार-बार माँग किये जाने पर सूची बनाने का कार्य बुनकर समिति ने ले लिया है। अभी हम लोग स्थानीय लोगों की मदद से 7725 लोगों की सूची बना पाये हैं और इन बुनकरों का बकाया 1 करोड़ 28 लाख रूपये है। हम लोग 20 हजार की सूची बनायेंगे जिसमें लगभग 4.50 सौ करोड़ रूपये बकाया आयेगा। 5 मई 2010 तक पूरी सूची शासन को भेज दी जायेगी। सरकार की मंशा बुनकरों के प्रति क्या है वो सामने आ जायेगा। बुनकरों के लाभ के लिए सरकार जितनी भी योजनाएँ चला रही है वो सभी योजना जल्द से जल्द बन्द होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी योजना सोसाइटी के द्वारा आती है और सोसाइटी कागज पर चलती है। किसी भी योजना का लाभ एक भी बुनकर नहीं पाता है। सारी योजनाओं को रोककर बुनकरों का सिर्फ बिजली का बकाया माफ किया जाय। बुनकर समाज का हित होने का यही एक रास्ता बनता है।

प्र0- आपकी बुनकर समिति के दबाव के कारण सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाया है?

उ0- बुनकर वेलफेयर संघर्ष समिति के दबाव से ही सरकार ने बुनकरों का बिजली बकाया सम्बन्धी आँकड़े और सूची माँगी है और सरकार ने पूर्णरूप से सर चार्ज माफ करने का फैसला शायद इसी वजह से लिया हो। सर चार्ज माफ होने से 10-15% बुनकरों को ही लाभ मिल पायेंगे। यह समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल तो बुनकर समाज की पूर्णरूप से बिजली बकाया माफी से ही निकलेगा। बिजली पर बुनकरों के सन्दर्भ में सरकार जुलाई 2010तक अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर पायेगी। जैसे किसानों का कर्ज माफ किया गया वैसे ही बुनकरों का भी कर्ज माफ किया जाना चाहिए।

प्र0- आपकी समिति की आगे की योजना क्या है?

उ0- बुनकर वेलफेयर संघर्ष समिति को कई लोगों ने सुझाव दिया है कि बुनकरों का कर्ज चुकता करने के लिए विदेशों से सहायता माँगी जाय। लेकिन हम सभी हिन्दुस्तानी हैं। हम अपनी सरकार से हीं सहायता लेंगे। इसके लिए बुनकर समाज बड़े से बड़ा आन्दोलन करने के लिए भी तैयार होंगे। वाराणसी कबीरदास की नगरी है। कबीरदास स्वयं बुनकर थें। उनकी सनद् को बचाने के लिए बुनकर समाज कुछ भी करने के लिए तैयार है। जब तक सरकार बिजली बकाया माफी का ऐलान नही करती तब तक बुनकर समाज का जीवन संकट ग्रस्त ही रहेगा।

हाजी रहमतुल्लाह अंसारी (प्रदेश संयोजक)
बुनकर वेलफेयर संघर्ष समिति
पीली कोठी वाराणसी, उ० प्र०

जौनपुर में किसानों का धरना प्रदर्शन

9 अप्रैल 2010 को भा0कि0यू0जौनपुर के महामंत्री राम सनेही पटेल के नेतृत्व में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर ब्लाक मुख्यालय मुंगरा बादशाहपुर पर धरना–प्रदर्शन किया गया। इस धरना–प्रदर्शन में लगभग 200 किसान शामिल रहें। फूलचन्द गौतम,डा0धर्मराज पटेल,रामसनेही पटेल,शिवप्रकाश सिंह,वी0एल0गौतम, जयवुनिशा, फूलचन्द तिवारी एवं सन्तोष कुमार संविज्ञ ने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता भा0कि0यू0जिला अध्यक्ष राजनाथ यादव तथा संचालन अमरनाथ यादव ने किया। पत्रक वी0डी0ओ0 के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा गया।

इस धरना प्रदर्शन में निम्न प्रमुख माँगें रखी गई।

1. किसानों को 16घण्टे बिजली दी जाय।
2. जिले की सभी नहरों में पानी पहुँचाया जाय।
3. प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम न्यायालय स्थापित किया जाय।
4. पुलिस प्रशासन बादशाहपुर में किसानों तथा किसान नेताओं का शोषण बन्द करे।
5. बादशाहपुर में खेल के मैदानों से अवैध कब्जे हटवाये जायें।
6. हाट-कुण्ड योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का शोषण बन्द किया जाय।
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाय।
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए एन एम द्वारा लड़का पैदा होने पर 500 रूपये तथा लड़की होने पर 200 रूपये अवैध रूप से लेना बन्द किया जाय।
9. बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्डधारकों का नाम बी0पी0 सूची में डाला जाय। जिससे वे सभी विकास की योजनाओं का लाभ ले सकें।

लोकविद्या पंचायत की ओर से गये संतोष कुमार संविज्ञ ने कहा कि किसानों को अपनी तत्काल की स्थानीय मांगों के अलावा व्यापक और दूरगामी समाधान के बारे मे भी विचार करना आवश्यक है। उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि राष्ट्रीय संसाधनों जैसे बिजली और शिक्षा में किसानो की बराबर की हिस्सेदारी बनाये बगैर किसान समाज का उत्पीडन बंद नही होगा।

अहरौरा में पावर हाउस पर किसानों का धरना

12 अप्रैल को मिर्जापुर जिले के अहरौरा पावर हाउस पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों का 18 दिनों से चल रहा धरना समाप्त हुआ। बिजली विभाग की मनमानी और बिजली कटौती की समस्यायें इतनी भीषण रही हैं कि गेहूँ की कटाई और मड़ाई के इन अति व्यस्त दिनों में भी किसानों ने इतना लम्बा धरना दिया। सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्र हुये और बिजली प्रशासन कम से कम 70 फीसदी बातें मानने को बाध्य हुआ। किसानों की मुख्य माँगे निम्नलिखित रही। धरने का नेतृत्व भा.कि.यू. के महासचिव- राजेन्द्र शास्त्री, प्रदेश सचिव- सिद्धनाथ सिंह, मण्डल अध्यक्ष- प्रहलाद सिंह, जिला अध्यक्ष- अली जमीर खाँ और वयोवृद्ध मार्गदर्शक डा. रामसागर सिंह ने किया।

मुख्य माँगे–

1. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली दी जाय।
2. अहरौरा फीडर पर शहरी क्षेत्र का बिजली का बिल लिया जाता है तो उतनी बिजली दी जाय। नगर को ग्रामीण शिड्यूल की बिजली दी जाती है तो ग्रामीण स्तर का बिल लिया जाय।
3. मनमाने बिजली बिल को सुधार कर जमा कराया जाय। बिल जमा कराने हेतु पासबुक सिस्टम लागू किया जाय।
4. ओ.सी.बी. दुरूस्त करायी जाय और रात्रिकालीन बिजली दी जाय।
5. अहरौरा और अदलहाट में क्रमशः 400 के.वी.ए. व 250 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाया जाय।
6. जर्जर तार व इन्सूलेटर डिस्क, कासआर्म बदले जायें। अधूरी पड़ी लाइनों को पूर्ण कराया जाय।
7. जले हुए ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जायें उस अवधि का बिल माफ किया जाय।
8. बड़े ट्रांसफारमरों पर टी.पी.एम.ओ. और जी.सी.बी. लगायी जाय और बत्ती का बिल दो महीने में लिया जाय। न जमा करने पर लाइन काट दी जाय।
9. आवासीय परिसर से लाइनों को हटाया जाय।
10. एस.डी.ओ. कार्यालय अहरौरा में स्थापित जाय।
11. बिल वसूली में ठिकेदारी प्रथा समाप्त की जाय। और उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बन्द किया जाय।
12. अहरौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण रूप से सुसज्जित कराया जाय। बिल्डिंग विभाग को स्थानान्तरित किया जाय। तथा एम्बुलेन्स की व्यवस्था करायी जाय।
13. धौहा व बड़ागाँव कान कास्ट आयरन फैक्ट्री विषैला धुआँ उगल रही है। उसे तत्काल बन्द किया जाय।
14. पलेवा रेट समाप्त किया जाय, नहरों की सफाई व मरम्मत करायी जाय।
15. बाठ सागर नहर परियोजना को जरगो बाँध से हुसेनपुर बीयर से जोड़ा जाय।
16. सोन लिफ्ट परियोजना को खाली समय में चलाकर डोंगिया जलाशय व अहरौरा बाँध को भरा जाय।
17. चुनार सिंचाई खण्ड का कार्यालय नरायनपुर में स्थापित किया जाय।
18. फसल बीमा का प्रिमियम किसानों से लिया गया है। जनपद सूखा घोषित है इसलिये फसल बीमा का लाभ दिया जाय।
19. चकबन्दी विभाग द्वारा किसानों का बड़े पैमाने पर आर्थिक व मानसिक शोषण बन्द किया जाय।

पाठकों से

1. **हर 50 रूपये पर 12 अंक दिये जायेंगे।**
2. **पंजीकरण की अर्जी दे दी गयी है। प्रक्रिया पूरी होने पर हर माह अंक निकाला जायेगा।**
3. **पंजीकरण तक हर दो माह में एक अंक सीमित प्रसार के लिए निकाला जा रहा है।**
4. **अपने विचार अवश्य भेजें।**
5. **अपने क्षेत्र के लोकविद्याधरों की समस्या, संघर्ष एवं संगठन के बारे में अवश्य लिख भेजें।**

निमंत्रण

बिजली ज्ञान पंचायत

सबको बराबर बिजली मिले

दिन- रविवार, 23 मई 2010, समय- दोपहर 12.00 से 4.00 बजे तक, स्थान- विद्या आश्रम, सारनाथ, वाराणसी

बिजली ज्ञान पंचायत बिजली और समाज से सम्बन्धित उन सभी ज्ञान, जानकारियों और समझ को सामने लाने का प्रयास है जिससे देश के सभी नागरिकों को बराबर की बिजली मिले इस उद्देश्य की ओर बढ़ने का रास्ता बने। सभी को बराबर की बिजली मिले इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक,संगठनात्मक व दार्शनिक सभी तरह के कामों की जरूरत है।

यह पंचायत सामान्य लोगों, किसानों, कारीगरों, महिलाओं, दुकानदारों, आदिवासियों, मजदूरों, सामान्य शहरी नागरिकों और विशेषज्ञों, जैसे- वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों,एन.जी.ओ. के नेताओं, बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, सभी को बराबरी का दर्जा देती है, सभी की बात को बराबर के महत्व का मानकर विमर्श का आयोजन प्रस्तावित करती है। विशेषज्ञ की विवरण की पेचीदगियों की जानकारी और किसान की इस्तेमाल की आवश्यकताओं व ट्रान्सफार्मर, कम व अनिश्चित आपूर्ति, रेट की समस्याओं आदि की जानकारी,कोई एक दूसरे से कम या अधिक महत्व की नही होती। बिजलीघर चलाने वाले वैज्ञानिक की जानकारी, राज्य विद्युत परिषद के प्रबन्ध निदेशक की जानकारी और गाँव-दराज में फैले हुये बिजली की समस्याओं से जूझते स्थानीय मरम्मतकर्ताओं की जानकारी, सब बराबर का महत्व रखती हैं। कोई पूरे प्रदेश की व्यवस्था देता है, तो कोई यह सुनिश्चित करता है कि बिजली वास्तव में मिले। किसी का सामाजिक पक्ष मजबूत है, तो किसी का तकनीकी पक्ष मजबूत है। इनमें आपस में किसी किस्म की ऊँच-नीच संगठन एवं नियमन में कमजोरियाँ ही पैदा कर सकती है और कुछ नहीं।

इस पंचायत में सभी किस्म के लोग भाग लेंगे। किसानों व कारीगरों के प्रतिनिधि होंगे, छात्रों, महिलाओं, मजदूरों और छोटे दुकानदारों के प्रतिनिधि होंगे,बिजली के उत्पादन और वितरण से जुड़े वैज्ञानिक,विभागीय अधिकारी,राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, एन. जी. ओ. सभी होंगे। हम इनमें उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता अथवा सामान्य जन और विशेषज्ञ का अंतर नही करेंगे।

पंचायत की बातचीत का प्रमुख संदर्भ होगा 'सबको बराबर बिजली मिले'। इसके साथ जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं और उनके हल की चर्चाओं को हम लोग निम्नलिखित ढंग से बाँट सकते हैं।

- वितरण से जुड़ी समस्यायें और उनके हल।
- वित्तीय समस्यायें-राजस्व, रेट, निवेश आदि।
- राष्ट्रीय एवं विकास सम्बन्धित बातें
- जीवन की गुणवत्ता के प्रश्न
- समान अवसर का सिद्धांत

इन सभी विषयों पर नीचे कुछ पँक्तियाँ दी जा रही हैं जिससे बातचीत के सार व विस्तार का संयोजन किया जा सके।

वितरण के बारे में अगर विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से पूछा जाय तो बहुत लम्बी सूची बन जायेगी। खम्भा न होना, तार टूटा होना, ट्रांसफार्मर जल जाना, बहुत कम समय की आपूर्ति, अनिश्चित कटौती, शहर और गाँव की आपूर्ति में बड़ा अंतर, पूर्णतया असुविधाजनक समयों पर आपूर्ति, लो वोल्टेज, बिजली चोरी, सरकारी दखलंदाजी, राजनैतिक नेताओं की दखलंदाजी, इत्यादि। हम एक छोटा-सा सर्वे कर रहे हैं जिसकी रिपोर्ट पंचायत में पेश की जायेगी।

सुना है वितरण और राजस्व आपूर्ति को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार की मात्रा देखते हुये रेट और राजस्व की सारी बातें ही बेमानी हो जाती हैं। बिजली उत्पादन में निवेश की समस्याओं का हल शायद बराबर के वितरण से ही शुरू होता हैं। इसी से वह दबाव बन सकता है जो वित्तीय समस्याओ को हल करने के लिये बाध्य कर दे।

देश की आजादी के पहले से ही विकास के दो रास्तों पर चर्चा रही है। एक यह कि कुछ लोग तेजी से आगे बढ़ें, खूब पढ़-लिख जायें और खूब पैसा कमायें और ऐसे लोगों के अभिक्रम से और लोगों के आगे बढ़ने के अवसर तैयार हों। और दूसरा यह कि सब लोग एकसाथ आगे बढ़ें, सब ढंग से पढ़ें लिखें, सबकी कमाई बढ़े, चाहे धीरे-धीरे ही क्यों न हो। इतिहास गवाह है कि पहले रास्ते से अधिकांश जनता बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से वंचित रह जाती है। सबको बराबर की बिजली, यह दूसरा रास्ता है।

बिजली से जीवन की गुणवत्ता जुड़ी है। उत्पादन की क्षमता और घर में प्रकाश, दोनो ही न हो तो वह जीवन कैसा? मनोरंजन के लिये भी बिजली चाहिये, पढ़ने और खाना बनाने के लिये, कम्प्यूटर के लिये, 1/2 हार्स पावर मशीन के लिये, खेतों में पानी देने के लिये और अब मोबाइल रीचार्ज के लिये भी। बिजली के बिना कोई जिन्दगी नही। बिजली आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन है और बराबरी का विचार आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा विचार। चाहे समाजवाद के दृष्टिकोण से देखें, चाहे मुक्त बाजार के, बिजली का बराबर का बँटवारा एक अनिवार्य शर्त के रूप में उभरता है, सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिये अथवा बराबरी के अवसर के सिद्धांत के हिसाब से।

उत्तर प्रदेश में और खासकर यहाँ के छोटे-छोटे शहरों, कस्बों और गाँवों में बिजली की हालत बेहद खराब रहती है। हमने तथ्यों की जाँच की तो पाया कि उत्तर प्रदेश में बिजली अन्य राज्यों से कोई बहुत कम हो ऐसा नही है। फिर क्या बात है? भ्रष्टाचार है, नीति गलत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, स्थानीय ढाँचा जर्जर है या खराब मशीनरी से भरा पड़ा है या फिर लोग सहयोग नही करते, बिल नही भरते, आपस में तालमेल नही रखते, या फिर और ही कोई बड़ी बात इसके पीछे है।

इन्ही सब बातों पर चर्चा और हल की खोज के लिये लोकविद्या पंचायत द्वारा किसान और कारीगर संगठनों के साथ मिलकर इस बिजली ज्ञान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आप सब आमंत्रित है। कृपया समय निकाल कर अवश्य आयें।

ज्ञान आंदोलन की वाहक ज्ञान पंचायत

वैश्वीकरण,अमेरिकी युद्धों और कम्प्यूटर व संचार की व्यवस्थाओं का आम लोगों की स्थिति पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसान,कारीगर,मज़दूर,पटरी के दुकानदार,सामान्य महिलायें,शहर की बस्तियाँ,आदिवासी और मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा,सभी त्रस्त हैं। ज्ञान आधारित समाज बनाने के नाम पर शोषण के नये तरीके अस्तित्व में आये हैं, डिजिटल विभाजन के रूप में समाज नये ढंग से विभाजित हो रहा है। विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त-करने-में-कठिन व संकीर्ण होती जा रही है। दुनिया भर के नौजवान इस स्थिति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।पिछले तीन वर्षों में यूरोप,अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका में छात्र संघर्षों की बाढ़ सी आ गई है। अफ्रीका और एशिया के नौजवानों में भी हलचल है।

दूसरी ओर कम्प्यूटर,संचार और मोबाइल के चलते नौजवानों के बीच एक आशा,जोश अथवा किसी किस्म की नई जिन्दगी का जज़्बा भी देखा जा सकता है। हालांकि यह जज़्बा अभी तो बाजार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बीच ही डोल रहा है,यह इस देश के विचारकों का कर्तव्य है कि इसे आम लोगों की स्थितियों और समस्याओं से जोड़ने के रास्ते खोजें। ये रास्ते,नई नीतियों,नई राजनीति और समाज व ज्ञान के नये तर्कों के रूप में सामने आयें। इस खोज का ज्ञान की दुनिया के साथ गहरा रिश्ता है। और ज्ञान की दुनिया का नौजवानों और आम लोगों के साथ कैसा सम्बन्ध है और होना चाहिए,यह इस खोज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।ज्ञान पंचायत का यह विचार एक ऐसी प्रक्रिया बनाने का विचार है जो परिवर्तन के कार्यकर्ताओं को विश्वविद्यालस के घिसेपिटे विचारों से बाहर निकलकर व्यवस्थित ढंग से सोचने का रास्ता दे।

ज्ञान के क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी की सिरमौर स्थिति अब सरकारी विभागों,राज्य के संकायों और विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा व अनुसंधान) तक सीमित रह गई है। स्वतंत्र विचारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं,निर्दलीय राजनैतिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच ज्ञान, तर्क और नीति के विचार साइंस की जकड़न से बाहर निकले हैं। कम्प्यूटर,मीडिया,भाषा,कला और मनोरंजन में भी खुलकर वैकल्पिक,यानि अन्य ज्ञान भण्डारों, तर्क की विधाओं,समझ व समीक्षा के मूल्यों आदि का इस्तेमाल बढ़ा है। इस सब के चलते ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हुआ है और नये मूल्यों व मानदण्डों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। ज्ञान और उसकी गतिविधि का सबसे बड़ा क्षेत्र लोक है,इसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है।

कृषि,स्वास्थ्य,भवन निर्माण,वानिकी,साहित्य समीक्षा,उद्योग, पदार्थ ज्ञान,प्राकृतिक क्रियायें,जल प्रबन्धन,उद्योग और बाजार प्रबन्धन,मनुष्य की समस्याओं और सक्रियता का अथवा प्रकृति का कोई भी क्षेत्र ले लें, वैकल्पिक विचार का एक सक्षम स्तम्भ और प्रक्रिया नज़र आयेगी। अधिकांश ऐसे विचार सरकारी नीतियों और बड़ी कम्पनियों की गतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं और जनप्रतिरोधों के संदर्भ में सामने आते हैं। अक्सर इन विचारों का जनता, उसकी जरूरत और उसकी समझ व सोचने के तरीके से गहरा सम्बन्ध होता है। प्रभावी मीडिया,सरकारी बंदरबाँट व प्रचारतंत्र,पूँजी प्रमुख आर्थिक सत्ता व विश्वविद्यालयों के विचार तंत्र के द्वारा वैकल्पिक ज्ञान के आधार पर प्रस्तावित तर्कों और नीतियों को हाशिये पर डाल दिया जाता है और उन्हें विस्तृत बहस में भी नही आने दिया जाता, अमल में लाने की बात तो दूर। किसी भी क्षेत्र विशेष या विशिष्ट समस्या के सन्दर्भ में दिये गये तर्क अलग-थलग पड़ जाते हैं, और उनकी वकालत करने वाले अपनी बात जरा भी मनवाने में असफल होते हैं। इस स्थिति को तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सक्षम सोच रखने वाले आपस में एक दूसरे का साथ दें। इससे ज्ञान और नीति के क्षेत्र में लोकपक्ष मज़बूत होगा। इसके लिए यह बिलकुल ज़रूरी नही है कि ये सब एक दूसरे की बात अथवा समझ को सही मानें। ज़रूरी यह है कि वे अपने को एक नये ज्ञान आंदोलन के सहभागी के रूप में देखें। ऐसे ज्ञान आंदोलन को आकार देने के लिए एक ज्ञान पंचायत का निर्माण होना चाहिए। इस ज्ञान पंचायत में वह ताकत हो सकती है जो उन समस्याओं और विकट परिस्थितियों को सुलझाने के रास्ते खोल सके जिनसे पूरे पूँजीवादी युग में मानवता त्रस्त रही है।

जिस तरह महात्मा गांधी ने बड़े उद्योगों को कटघरे में खड़ा कर दिया था, आज सूचना के पूँजीवादी युग में विश्वविद्यालय को कटघरे में खड़ा करना ज़रूरी है। जिस तरह फ्रांसीसी प्रबोधन ने चर्च और उसके ज्ञान को कटघरे में खड़ा कर दिया था, उसी तरह आज विश्वविद्यालय और उसके ज्ञान को कटघरे में खड़ा करना ज़रूरी है। विश्वविद्यालय पूँजीवादी युग का सबसे कीमती निर्माण है। विश्वविद्यालय में जिस ज्ञान का निर्माण होता है, उसी के आधार पर यह प्रकृति का नाश करने वाली और महागरीबी का निर्माण करने वाली व्यवस्था चलती है। विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष और परोक्ष चहारदीवारियों के मार्फत विचार के रास्ते बन्द करता है। किन्तु विचार करने वाले के रास्ते कभी बन्द नहीं होते। व्यक्तिगत स्तर पर अथवा समूह, क्षेत्र, राष्ट्र या विश्व के स्तर पर जिसने भी इन रास्तों को खोलने का प्रयास किया है, वे सब ज्ञान पंचायत में शामिल होने चाहिए। ज्ञान पंचायत ज्ञान की जन सुनवाई है। ज्ञान पंचायत दर्शन को सामाजिक शक्ति का रूप देने का एक औजार है। इसके मार्फत एक नई दुनिया का ज्ञान आधार तैयार किया जाना चाहिए। समाज में आमूल परिवर्तन की यह मांग है कि ज्ञान की दुनिया में क्रांति हो। ज्ञान पंचायत एक ऐसी ही क्रांति की वाहक है।

बिजली के तारों से फसल जली

बिजली विभाग के ज़ुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। किसान को बिजली मिलती नहीं, ऊपर से मनमाना बिजली भाड़ा वसूला जा रहा है। किसान के खेत से गुजरने वाली हाइटेंशन तार किसान को बिजली तो नहीं देती पर उसकी फसल को आग लगा दे रही हैं। इस वर्ष कई जगह किसानों के खेतों में खड़ी या कटी रखी फसल राख में तब्दील हो गई, कारण रहा बिजली की अव्यवस्था। चौबेपुर में 22 बीघा फसल जल गई। बराई, भगतुआ, उमरहाँ, बसैली में कुल 15 बीघा फसल इसी तरह आग में स्वाहा हो गई। बबुरी में 20 एकड़, आराजी लाइन के दरेखू गाँव में, सैयदराजा, रानी की सराय, बड़ागाँव, मिर्जामुराद, हरहुआ में लगभग 35 बीघा फसल जल गई। चन्दौली, राबर्ट्सगंज, धीना, गाजीपुर, सैदपुर में फसलों में आग लगने की घटनायें हुईं। मऊ में बिजली के तार गिरने से फसल जल गई तो किसानों ने क्रोधित होकर मऊ-बलिया मार्ग जाम कर दिया।

गाँवों में बिजली समस्याओं का संकलन भारतीय किसान यूनियन का अभियान

भा.कि.यू. की वाराणसी इकाई ने गाँव के कुछ चुने हुये बाजारों में रखे रजिस्टरों में गाँववासियों द्वारा अपने गाँव की बिजली से सम्बंधित समस्याओं को दर्ज कराने का अभियान चला दिया है। गाँव वालों की कलम कहती है कि गाँवों में कहीं बिजली के तार नहीं है, कहीं खम्भा नहीं है तो कहीं ट्रांसफार्मर नहीं हैं। कहीं ट्रांसफार्मर है तो जल गया है, बिजली की अनिश्चितता, कम घंटे के लिए मिलना, लो वोल्टेज आदि से गाँव के किसान, कारीगर, पढ़ने वाले बच्चे और गृहणियाँ सभी परेशान हैं। मशीनें खराब हो रही हैं। रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है । इसके बावजूद बिजली का बिल मनमाना चला आता है। कमौली, कोटवाँ, बभनपुरा, सुलतानपुर, राजापुर, रामचन्दीपुर, नवापुरा, व्यासपुर, बरियासनपुर, छितोना, सरैयां, सलारपुर, पतेरवाँ व सारनाथ के किसानों और कारीगरों ने अपने गाँवों की बिजली की समस्याओं को दर्ज कराया है। यूनियन ने तय किया है कि यह अभियान जारी रहेगा।

बिजली कटौती से गेहूँ की मड़ाई हुई महंगी

ग्रामीण क्षेत्र में बिजली न मिलने से किसान ट्रैक्टर से मड़ाई कराने को मजबूर हैं । टैक्टर या डीजल इंजन से गेहूँ की मड़ाई के लिये किसान को बिजली की तुलना में अधिक खर्च करना पडता है और दूसरे के निजी संसाधनों पर निर्भर रहना पडता है।

सम्पादकीय

आखिरकार यह देश किसका है ?

शिक्षा के क्षेत्र में दो बातें जोरो पर हैं। एक यह कि उच्च शिक्षा के शीर्ष संस्थानों की संख्या में बड़ी बढ़ोत्तरी हो और दूसरी यह कि सभी स्कूल जा सकें इसकी व्यवस्थायें पुख्ता हो। जबकि पहले बिन्दु पर मानव संसाधन मंत्रालय लगातार नये-नये कदम उठा रहा है, दूसरे बिन्दु पर शिक्षा के अधिकार का एक नया कानून प्रस्तावित है जिसका अधिकांश सामाजिक कार्यकर्त्ता इस बिना पर विरोध कर रहे हैं कि वह इतना खोखला है कि सभी को शिक्षा मिल पाये इसका रास्ता उससे खुलने वाला नहीं है। सामाजिक कार्यकर्त्ता उच्च शिक्षा संस्थानों का

विरोध क्यों नही करते? जबकि दोनों ही कदम एक ही शिक्षा नीति के परस्पर पूरक पक्ष हैं। अगर सरकार की शिक्षा नीति में खोट है, अगर यह शिक्षा नीति चन्द लोगों को आधुनिकतम् जीवन की ऊँचाइयों तक पँहुचाने वाली है और करोड़ों-करोड़ बच्चों को शिक्षा से वंचित ही रखने वाली है, तो इसका समग्र विरोध क्यों नही होता?

दो साल पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 200 से बढ़ाकर 1500 कर देने की बात की थी। तब से नये-नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुले हैं और उच्च शिक्षा के निजी संस्थानों में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। हाल में विदेशी विश्वविद्यालयों व एजेन्सियों को इस देश में प्रवेश की अनुमति की नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। पिछले दो दशकों में देश भर में इंजीनियरिंग और मैनेजमेन्ट के कालेजों की बाढ़-सी आ गई है। बड़े उद्योगों और बड़े निगमों के वरिष्ठ प्रबन्धकों का कहना है कि इन कालेजों से निकले छात्र नौकरी करने लायक नही होतें। उन्होंने कुछ सीखा ही नही होता। हम अभी इसके सही गलत की जाँच में नहीं पड़ रहे हैं और कहना यह चाहते हैं कि बड़ी तादाद में मैनेजमेंट व इंजिनीयरिंग के ये कालेज उच्च शिक्षा के ऐसे स्थान हैं जो उच्च शिक्षा के शीर्ष संस्थानों से एकदम अलग हैं तकनीकी दृष्टिकोण से वे उच्च शिक्षा के स्थान तो हैं लेकिन बाजार में उन्हें उच्च शिक्षा के संस्थान की मान्यता प्राप्त नहीं है। उच्च शिक्षा के शीर्ष स्थान वे हैं जहाँ पैसा, कम्प्यूटर और इंटरनेट, विदेश जाना-आना, अंग्रेजी, महानगरीय संस्कृति और पास होते ही लाखों की नौकरी की इफराती है। इस तरह की इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस, विधि, प्रबन्ध शास्त्र और कला, डिजाइन, फैशन आदि सब मिलाकर देश भर में लगभग 100 जगहें होंगी और यहाँ से पास होकर निकलने वाले छात्रो की प्रति संस्थान प्रति वर्ष संख्या अगर औसत 300 भी हो, तो साल में 30,000छात्र-छात्रायें इन जगहों से निकलते हैं। यानि 10 साल में तीन लाख। ये संख्यायें बहुत बढ़ भी जायें तो अगले 10 साल में तीन लाख की जगह ऐसे छः लाख विधार्थी इन जगहों से निकलेंगे। यह देश सवा-सौ करोड़ का है और मोटा हिसाब भी करें तो इन 10 वर्षों में 20-30 के आयु वर्ग से गुजरने वाले नौजवानों, लड़के और लड़कियों की संख्या 20-25 करोड़ तो हो ही जायेगी। यानि हर 1000 नौजवानों में 3 या 4 बच्चे इन संस्थानों से गुजर कर निकलेंगे। क्या संख्याओं के इस अनुपात के बाद भी इस शिक्षा नीति के पक्ष में कोई तर्क बचा रह सकता हैं?आखिरकार यह देश किसका है? 'काबिल और लाखों के लायक' इन युवाओं के बल पर दुनिया मे इस देश की एक अग्रणी स्थिति बनाने का विचार देश के भविष्य को एक प्रतिशत से भी कम लोगो के हाथों में सौंपता है। आजादी के बाद से शिक्षा नीति के रुप में सामने आया यह सबसे संकीर्ण विचार है। यह तो आपराधिक हदें पार कर रहा है

वर्तमान शिक्षा नीति का समग्र विरोध अति आवश्यक है। इस शिक्षा नीति का भी वही रास्ता है जो किसानों और आदिवासियों से जमीनें छीनने का रास्ता है और जो मॉल और महलों जैसे निजी अस्पतालों को बनाने का रास्ता है। शिक्षा नीति का विरोध करने वालों को शिक्षा के सवाल तक पहुँचने के पहले ज्ञान का सवाल उठाना होगा। अगर वही ज्ञान है, जो उच्च शिक्षा के इन शीर्ष संस्थानों और बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में पनपता है तो शिक्षा नीति यही बनेगी जो बन रही है। अगर किसान, कारीगर, अदिवासी और महिलाओं के सामान्य तौर-तरीकों, उत्पादन, प्रबन्ध और व्यवस्थाओं की उनकी जानकारियों, समाज से उनके रिश्तों, उनके सोचने के तरीकों, उनके संगठन और तर्क की विधाओं को भी ज्ञान का बराबर का दर्जा मिले, तो शिक्षा कहाँ हो, कैसे हो, किस चीज की हो, कितनी हो, किसके लिये हो आदि सभी पर विचारों का एक नया भण्डार खुल जायेगा, देश की प्रगति के नये रास्ते उजागर होंगे, ऐसे रास्ते जो सबकी भागीदारी के होंगे, सबके बीच बराबरी के होंगे और सबकी खुशहाली के होंगे।

कौन सी वार्ता चाहिए?

मध्य पूर्व भारत में लड़ाई की स्थितियाँ बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार और बंगाल में सरकार के केन्द्रीय और प्रान्तीय बलों द्वारा आपरेशन ग्रीन हंट चलाया जा रहा है और इसका जवाब माओवादी दे रहे हैं। दोनो तरफ के लोग मर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों का लम्बे समय से जिस तरह शोषण और दोहन हुआ है, जंगलों और जमीनों पर कब्जा किया गया है, और आदिवासियों को भूखमरी में धकेलकर दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर बना दिया गया है, उस सबका और क्या नतीजा हो सकता था? लड़ाई तेज होने से मौलिक प्रश्नों पर भी बहस तेज होनी चाहिए। पर ऐसा हो नही रहा है। मीडिया का कमाल कहिये या हमारी राजनीति का खोखलापन, अपने ही देश के करोड़ों लोगों की जिन्दगी की तबाही पर हम शान्ति और हिंसा के सवालों को ही ज्यादा तरजीह देते आ रहे हैं। जरूरत है बुनियादी सवालों पर खुली और आम बहस की।

क्या माओवादी गाँधी से वार्ता करना चाहेंगे? आज गाँधी उन लोगों के कब्जे में है जो मॉल बाजार बनाते हैं, करोड़ की आबादी के शहर बनाते हैं, बड़े-बड़े उद्योग बनाते हैं, जंगलों को काटने और नदियों को बाँधने के उपक्रम करते हैं, नाभिकीय बम बनाते हैं और किसानों, दस्तकारों और आदिवासियों को गरीबी के सबसे निचले पायदान पर धकेलते जाते हैं। विनोबा और उनके चेलों ने जो समझौते किये उसके नतीजे साफ हैं। गाँधी जिस अन्तिम मनुष्य की लड़ाई लड़ रहे थें, उस अन्तिम मनुष्य की लड़ाई तो आज माओवादी लड़ रहे हैं और किसानों के संगठन लड़ रहे हैं। भारत में बुनियादी परिवर्तन और गरीबों के उद्धार के रास्तों को गाँधी से अपना रिश्ता तय करना होगा। हम यह मानते है कि मार्क्स और गाँधी ऐसे विचारक हुए हैं जिनमें पूँजीवाद की समग्र समझ रही है। चाहे उनके दृष्टिकोण और समझ का विस्तार सर्वथा अलग ही क्यों न रहा हो।

1980 से, जब हम 'मजदूर किसान नीति' के मार्फत किसान आन्दोलन के बीच खड़े हुआ करते थे, हम यह तर्क दिया करते थे कि इस देश के बहिष्कृत समाज (किसान, कारीगर, महिला और आदिवासी) के उद्धार के विचारों में सही धार व संतुलन बनाने के लिए मार्क्स और गाँधी के बीच वार्ता और सेतु की जरूरत है। किसान आन्दोलन में हम वह क्षमता देखते हैं जो इस कार्य का माहौल बना सके। आज भी किसान आन्दोलन की कार्य सूची में हम इसे रखते हैं। माओवादी यदि गाँधी से वार्ता करते हैं, तो इस देश की राजनीति में ऐसा नयापन आयेगा जिसके बारे में आप अभी सोच भी नही सकते।

बृहत् समाज के कष्टों और शोषण की जो स्थिति है उसे शब्दों में बाँधना मुश्किल है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सांस्कृतिक व सामाजिक सम्मान, अपनी पहल के मौके, कुछ भी नहीं है और उल्टे इन लोगों के जीवन के साधनों का छीना जाना, इनके श्रम और विद्या का शोषण बदस्तूर जारी है। इन स्थितियों से उबरने के 20 वीं सदी के सभी मॉडल अपना दौर पूरा कर चुके हैं और एक नई सोच की जरूरत है। ऐसी नई सोच का एक स्रोत गरीबी और गैरबराबरी के खिलाफ लड़ने वाले संगठनों की विचारधाराओं के आपसी अंतर्विरोध के रचनात्मक पक्ष में भी होना चाहिये।

यह वार्ता एक, दो या तीन सबसे महत्वपूर्ण समझे जा रहे बिन्दुओं में समेटी नही जा सकती। अहिंसा-हिंसा, गाँव-शहर, बहिष्कृत समाज-पश्चिमीकृत समाज या और किन्हीं बिन्दुओं में इस वार्ता को समेटा नही जा सकता। माओ के विचारों और गाँधी के विचारों को समग्र भाव में ही एक फलदायक वार्ता में बुना जा सकता है। इस देश की जनता के हित में यह वार्ता जितनी सबल बने उतना ही अच्छा है।

संसद की संरचना क्या हो ?

चौदह वर्षो से देश की संसद में महिला आरक्षण बिल को लाया जा रहा है और अभी तक इस पर सहमति नही बन पा रही है। इस बार भी शायद ही इस पर सहमति बने। विरोध के प्रखर स्वर की अगुवाई उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख दलों ने की है। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव, जनता दल (यू) के शरद यादव ने विरोध किया है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती व तृणमूल कांग्रेस की ममता बैनर्जी ने भी विरोध किया है। ये दल शुरू से ही इस बिल का विरोध करते आ रहे हैं। इनका तर्क है कि पिछड़े, दलित व मुसलमान वर्गों की महिलायें इस आरक्षण का फायदा उठाने में अभी सक्षम नही हैं और ऐसे में संसद में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व घटेगा और इन घटकों को हानि होगी। जो पार्टियाँ मुखर स्वर में इस बिल का समर्थन कर रही हैं उनमें भी अंदर काफी विरोध है। महिलाओं के हित को वरीयता देने की सोच एक प्रगतिशील सोच है, ऐसा मानने वाले स्त्री-समुदाय को किसी अन्य पहचान से रहित एक ऐसा समुदाय मानते हैं जिसके वर्गीय, जातीय (सांस्कृतिक) आदि हित समान है। ऐसी सोच में लोकतंत्र के मौलिक विचार को वे कितनी तरजीह दे रहे हैं ये उन्हें सोचना होगा।

हमारा संसदीय लोकतंत्र प्रतिनिधित्व की अवधारणा पर आधारित है और आरक्षण की अवधारणा कमजोर व पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की है। इसलिये विरोध का यह प्रखर और व्यापक स्वर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने लोकतंत्र की बुनियाद पर नये सिरे से सोचने का रास्ता खोलता है ।

जहाँ तक पिछड़े व कमजोर वर्गों की पहचान का सवाल है उस पर पुनर्विचार होने की जरूरत है। नई आर्थिक नीतियाँ, वैश्वीकरण और नये तकनीकी प्रसार के चलते समाज के बहुत से घटक पिछड़े और कमजोर तबकों में तब्दील हो गये हैं। इनमें मजदूर, किसान और कारीगर मुख्य हैं। अगर स्त्री-समुदाय को एक वर्ग के रूप में देखते हुये आरक्षण की वकालत की जा रही है तो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और कारीगर वर्ग को भी आरक्षण दिया जाना चाहिये। चूँकि संसद और विधायिकायें नीति नियामक संस्थायें हैं और यहाँ देश की जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन को आकार देने वाली नीतियाँ बनती हैं, ऐसे में इन वर्गों का वहाँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है। यह न भूलना चाहिये कि पिछले 15-20 वर्षों में किसान, कारीगर, मजदूर और आदिवासी समाजों के हितों के खिलाफ एक के बाद एक नीतियाँ हमारे संसद में बनी हैं और जिसका नतीजा है किसान और कारीगर परिवारों में आत्महत्या और भूखमरी की घटनाओं का सिलसिला। ऐसे मे इन वर्गों का संसद में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना आवश्यक है। फिर, इन वर्गों की स्त्रियाँ अपने वर्ग के समाज से अलग नही हैं। कोई भी सामाजिक विचार हमें ऐसा देखने की सलाह नही देता और अगर देगा तो वह सामाजिक विचार कैसे रह पायेगा? सम्पन्न पढ़े-लिखे वर्ग की महिलाओं और कमजोर/पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक हितों में बड़ा विरोध है और इस विरोध को पहचाना जाना चाहिए। ऐसे में बिल का विरोध करने वालों की यह माँग कि महिला आरक्षण में पिछड़े व कमजोर वर्ग के महिलाओं का कोटा सुनिश्चित हो, एक हल हो सकता है, लेकिन इसके पहले मजदूर, किसान और कारीगर वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की जरूरत है।

इस तरह विधायिकाओं में महिला आरक्षण की बहस ने संसद की संरचना क्या हो इस पर बुनियादी बहस और बदलाव का मौका तैयार किया है। हालाँकि, इतना बड़ा सवाल कोई भी दल नही उठा रहा है जिसका एक ही कारण हो सकता है कि कोई भी दल पूरे समाज और देश के बारे में नही सोच रहा है। वे केवल अपनी पार्टी और उसके जनआधार के राजनैतिक हितों के बारे में ही सोचते मालूम पड़ते हैं। राजनैतिक दलों से स्वतंत्र कार्य करने वाले संगठनों को सामने आना चाहिए और भारतीय संसद की संरचना के बुनियादी सवाल को सार्वजनिक करना चाहिए।

लोकविद्या पंचायत के सदस्य बनें

1. वार्षिक सदस्यता शुल्क – रुपये 50 मात्र।
2. आजीवन सदस्यता शुल्क – रुपये 1000 मात्र।

सम्पर्क करें–

विद्या आश्रम, सा. 10/82 ए, अशोक मार्ग
सारनाथ, वाराणसी-221007,
फोन – 0542-2595120

विकासशील जन-संघर्ष

कहते हैं कि 1990 में प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाने गये इराक में किये गये अमेरिकी सैनिक हमले से एक नया साम्राज्य बनाने की शुरुआत हुई। कम्प्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी व वैश्वीकरण की आर्थिक नीतियाँ प्रमुख रूप से इसी साम्राज्य के निर्माण के औजार हैं। दुनियाभर के बाजारों और जमीनों पर कब्जा इसी साम्राज्य के निर्माण के हिस्से हैं। इराक और अफगानिस्तान में लगातार चल रहे युद्ध और नाभिकीय खतरों के हवाले ईरान और उत्तर कोरिया को दबाने की नीतियाँ इसी अमेरिकी साम्राज्य को बनाने के सामरिक घटक हैं। 'गूगल' नाम की इन्टरनेट कम्पनी का चीन में अपनी स्वतंत्रता का दावा इसी साम्राज्य को बनाने का गैर-राष्ट्रीय दिखने वाला कदम है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है तो अमेरिका की सरकार चिंता व्यक्त करती है और अपनी दखल का हक जाहिर करती है। यह कहने के लिये शायद किसी तर्क की ज़रूरत नहीं है कि यह एक सर्वथा अवांछनीय और मनुष्य के बुनियादी मूल्यों के हनन की प्रक्रिया है। इसी साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया ने एक बार फिर बहुत जोर से दुनियाभर में संसाधनों और वित्तीय व्यवस्थाओं पर कब्जा करने की मुहिमें चला रखी हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नये-नये अनुसंधान, दुनियाभर के फुटकर बाजारों पर नियंत्रण और तीसरी दुनिया के देशों में जमीनों पर नये सिरे से कब्जा यह सब इसी का हिस्सा है।

किसी भी सोचने-विचारने वाले व्यक्ति के सामने सवाल ये उठता है कि ऐसी ऐतिहासिक ज्यादती के खिलाफ आवाजें कहाँ उठ रही हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पिछले 10 वर्षों में इस प्रक्रिया के खिलाफ तरह-तरह की आवाजें उठी है और संघर्ष हुये हैं। उनमें हम विशेष रूप से चार धाराओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

1. **आदिवासियों के संघर्षः** उड़ीसा, झारखण्ड, छतीसगढ़, बंगाल और मध्य प्रदेश के आदिवासी उनकी जमीनों पर कब्जे, जंगलों से बेदखली और बड़े बाँधों के चलते विस्थापन के खिलाफ संघर्षरत हैं। युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी के कछार के आदिवासी उद्योगों के लिये जमीनों के अधिग्रहण के खिलाफ सतत् मोर्चेबन्दी में हैं। पेरू नाम के देश में पिछले वर्ष एक बहुत बड़े संघर्ष में पुलिस ने अनेक आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। मैक्सिको के आदिवासी झपाटिस्टा नाम के संगठन के नेतृत्व में स्वराज की लड़ाई लड़ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के ही बोलिविया नाम के देश में आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हाल में पृथ्वी को माँ समझने और मानने के विचार के अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन के सवाल पर एक बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। आदिवासियों के संघर्ष सभी जगह उठाव पर हैं।
2. **नया वामपंथ :** दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में पिछले 10 वर्षों में वामपंथी रूझान रखने वाली सरकारें अस्तित्व में आयी हैं। ये सब अमेरिका विरोधी हैं। वेनेजुएला के वामपंथी राष्ट्रपति हूगो शावेज ने इसी वर्ष एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन भी बुलाया है। ब्राजील से शुरु हुआ विश्व सामाजिक मंच, जिसका एक बहुत बड़ा महाधिवेशन जनवरी, 2004 में मुम्बई में हुआ था, एक मोटे तौर पर वामपंथी रूझान का अमेरिका विरोधी जमावड़ा है। यूरोप का छात्र आंदोलन वामपंथी रूझान का उच्चशिक्षा में बुनियादी परिवर्तन का आन्दोलन है। ये सब वामपंथी विचार मूलतः अपनी धरती की वास्तविकताओं से ही प्रेरित हैं। आदिवासियों के संघर्षों के साथ इनका दोस्ती का रिश्ता है।
3. **इस्लामवादी संघर्ष :** 21वीं सदी का पहला दशक इस्लामी उग्रवाद द्वारा अमेरिका को दी गई चुनौती से भरा हुआ है। इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम में चल रहे अमेरिकी युद्ध इसी चुनौती का नतीजा है। ईरान का शासन भी अमेरिकी तानाशाही को सतत् चुनौती देता आ रहा है। यह भी अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी प्रतिपक्ष का ही एक रूप है।
4. **भारत का किसान आन्दोलन :** अब तीन दशक से चल रहा यह किसान आन्दोलन मोटे तौर पर गाँव बनाम शहर की वास्तविकता और वैचारिक स्थापना पर टिका हुआ है। इसका महत्त्व इसमें है कि यह सैद्धान्तिक स्तर पर भी गाँव को एक न्यायसंगत समाज की पुनर्रचना का केन्द्र मानता है। अपने मूल्यों और संघर्ष के रूपों में यह गांधी के नजदीक है। हालाँकि किन्हीं प्रकट अर्थों में यह आन्दोलन राजनीतिक नहीं है लेकिन इसीलिये एक दूरगामी, वर्तमान व्यवस्थाओं से मुक्ति की राजनीति का वाहक बनने की संभावना संजोये हुये है।

अमेरिकी साम्राज्य को चुनौती का आधार उस ज्ञान की परम्परा में नहीं हो सकता जिसका खुला नेतृत्व आज अमेरिका के ही हाथ में है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के लोगों की, किसानों, दस्तकारों और आदिवासियों की अपनी ज्ञान की परम्परायें हैं, लोकविद्या की परम्परायें हैं। इनका अपना जीवंत ज्ञान है जो उनकी दुनिया संचालित करता है। आदिवासियों और किसानों के संघर्षों में अपने ज्ञान को फिर से सार्वजनिक प्रतिष्ठा दिलवाने की ताकत है। यही वह प्रक्रिया है जिससे वामपंथ, गांधी और इस्लाम सभी पुनः परिभाषित किये जा सकेंगे। अमेरिकी साम्राज्य को चुनौती की माँग इससे छोटी नहीं है, और भी बड़ी जरूर हो सकती है।

–सुनील सहस्त्रबुद्धे

लोकविद्या की समाजदृष्टि

1. सभी को अपनी विद्या के बल पर जीवन चलाने का मौलिक अधिकार हो।
2. कृषि उत्पाद को जायज़ दाम हो।
3. राष्ट्रीय संसाधनों का गाँव और शहर में बराबर का बँटवारा हो।
4. घर-घर में उद्योग हो।
5. स्थानीय बाजार को संरक्षण हो।
6. अधिकतम और न्यूनतम आय में 5:1 से अधिक का अनुपात न हो।
8. गाँव-गाँव में मीडिया स्कूल हो।
9. उच्च शिक्षा के दरवाजे सबके लिये खुले हों।
10. लोकविद्या को विश्वविद्यालय के ज्ञान के बराबर का दर्जा हो।

किसान, कारीगर, आदिवासी, छोटा दुकानदार एक हों

क्योंकि

सूचना युग में कम्प्यूटर-इंटरनेट और वैश्वीकरण मिलकर किसानी, कारीगरी, छोटी दुकानदारी को उजाड़ रहे हैं, मज़दूरी को घटा रहे हैं।

कैसे?

1. इनके श्रम को बाजार में कम दाम देकर
2. इनके ज्ञान यानि लोकविद्या को लूटकर
3. शिक्षा को महंगी बना कर व इन्हें नये ज्ञान से वंचित कर

आइए

1. लोकविद्या के बल पर जीविका के अधिकार का दावा करें।
2. सूचना युग में श्रम और ज्ञान की लूट को रोकने के उपाय खोजें।
3. बाजार और ज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोषण की समझ और विरोध को आकार दें।

किसान विरोधी बजट

इस साल के अपने बजट भाषण के अन्त में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि यह बजट आम आदमी का है। यह बजट किसान, उद्यमी और निवेशकर्ता का है। वित्त मंत्री का यह कथन निश्चित ही गुमराह करने वाला है। उन्होंने किसान, कारीगर और असंगठित मजदूरों की आँखों पर पर्दा डालने का काम किया है। उनका कहना सच तभी होता जब वे समाजवाद के सरल सिद्धान्त के अनुरूप अमीरों पर कर लगाते और गरीबों के मदद की नीतियाँ बनाते।

बजट के पहले यूरिया के दाम 10% बढ़ाकर उन्होंने बड़ी चालाकी से किसान की जेब से 6,000 करोड़ रूपया निकाल लिया। यह तब जब पिछले साल के बजट में उन्होंने यह वादा किया था कि खाद पर दी जाने वाली इमदाद (सब्सिडी) सीधे किसानों को दी जायेगी।

सरकार जब भी वित्तीय सुधार की बात करती है हमेशा किसान और असंगठित क्षेत्र पर नये बोझ डालती है। इस बजट में अमीरों पर कर बढ़ाने की जगह उन्हें करों में खूब छूट दी गयी है। सालाना 8 लाख या उससे ज्यादा कमाने वालों के कर में इस साल 50,000 रू0 की कमी की गयी है।

आजादी के 62 साल बाद 65% आबादी गाँव में रहती है और कृषि पर निर्भर है। वित्त मंत्री ने यह माना है कि कृषि विकास की दर मात्र 2 फीसदी है।

पिछले साल के बजट में 70,000 करोड़ रूपये की कर्ज माफी करके सरकार ने कृषि संकटग्रस्त है यह माना। इस वर्ष वित्त मंत्री ने यह माना कि वर्षा न होने के कारण इस साल की खरीफ की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। यह एक तथ्य है कि अपने देश के 70 फीसदी किसान बरसात पर निर्भर हैं और खरीफ में ही उनके जीवन का आधार होता है। असिंचित जमीनों के किसान प्रकृति और बाजार की अनिश्चितताओं से हमेशा ही मोर्चा उठाते रहते हैं। सरकार ने किसी ऐसे बीमे की घोषणा नही की जो उनकी न्यूनतम आय और नुकसान की भरपाई करता। असिंचित जमीनों पर अब नवम्बर 2010 में ही अगली फसल आयेगी। इसलिये जून 2010 तक के लिए कर्ज वापसी के स्थगन का कोई अर्थ नही है।

मैं यह मानता हूँ कि मुखर्जी मोशाय ने बरसात पर निर्भर खेती के लिए विशेष नीतिगत समर्थन की हमारी लम्बे समय की माँग को मान्यता दी। उन्होंने घोषणा की कि बरसात पर निर्भर जमीनों पर तिलहन और दलहन की खेती के लिए 60,000 गाँव चुने जायेंगे और इसके लिए 300 करोड़ रू0 आवंटित किये। इस हिसाब से हर गाँव पर 50,000 रूपये आत हैं। देखिये, कर व्यवस्था में व्यक्तिगत स्तर पर जहाँ 80,000 रूपये तक की छूट मिली है वहीं पूरे के पूरे गाँव के लिए मात्र 50,000 रूपये का आवंटन किया गया है।

वित्त मंत्री ने खाने का दाम बढ़ने की बात तो की है, किन्तु यह बढ़ोत्तरी कितनी है इस पर वे चुप हैं। छठे वेतन आयोग और उद्योगों के उत्प्रेरक पैकेज के बाद से पैसों की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी हुई है। उसी अनुपात में गाँव में पैसों की आपूर्ति यदि नही बढ़ी तो गाँव और शहर के बीच का अन्तर बढ़ना तय है। यदि हम चाहते हैं कि ऐसा न हो तो दामों पर नियंत्रण और उसका लाभ किसान तक पहुँचना जरूरी है।

वित्त मंत्री कह रहे हैं कि उत्पादन में वृद्वि करके आपूर्ति बढ़ायी जाये तो दाम कम होंगे। यानि यह कहना अतिशयोक्ति नही होगा कि अपने देश में किसान का भविष्य हैः **उत्पादन करो और मर जाओ।**

बजट में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाये गये हैं इससे किसानों के खर्च बढ़ेंगे। उसके लिए क्या किया जायेगा इस पर वित्त मंत्री चुप हैं। बजट में भण्डारण, प्रसंस्करण, ठण्डा रखने के इन्तजाम पर जोर है और उसके लिए धन आवंटित किया गया है। पिछले 62 साल का अनुभव यह बताता है कि इससे किसान को कोई फायदा नही होता। सारे फायदे प्रसंस्करण उद्योग और बाजार के व्यवस्थापक उठा ले जाते हैं। किसान को वही मिलता है जो कम से कम देना जरूरी हो। इस सबके सन्दर्भ में हमें यह मानना चाहिए कि बरसाती खेती को सीधा आर्थिक समर्थन दिया जाय। किसान आयोग के अध्यक्ष एम. एस. स्वामीनाथन का प्रस्ताव है कि कृषि में विकास का मानक उत्पादन में वृद्धि में नही होना चाहिये बल्कि उसे किसान की आय में वृद्धि से जोड़ा जाना चाहिए।

पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि का कारण वित्त मंत्री ने यह बताया है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े तो सरकार ने एक्साइज कर कम कर दिया और अब जब वे दाम गिरे हैं तो यह कर दुबारा लगा दिया गया। मेरा सवाल यह है कि यही तर्क खाद्य तेलों और कृषि उत्पाद पर क्यों नही लागू किया जाता?

जब पाम आयल (तेल) का दाम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 1400 डालर प्रति टन था तब भारत सरकार ने उस पर लगने वाला आयात कर खतम कर दिया, 85 फीसदी से घटा कर शून्य कर दिया और अब जब पाम आयल के राष्ट्रीय दाम घटकर 800 डालर प्रति टन हो गये हैं तो उस पर दुबारा आयात कर क्यों नही लगाया जाता?

अगर हम विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित राशियों और इन राशियों के वितरित करने के नियमों इत्यादि को देखें तो पायेंगे कि हमेशा ही शहरीकरण और उद्योगों को ज्यादा पैसा दिया जाता है। उदाहरण के लिए इस बजट में तिरूपुर के कपड़ा उद्योग को रूपया 200 करोड़ दिया गया है लेकिन बरसात पर निर्भर कपास के किसान पर कोई ध्यान नही दिया गया है।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि प्रत्यक्ष कर के जरिये सरकारी कोष की आमद में 26,000 करोड़ रूपये की कमी आयेगी। जबकि परोक्ष करों के मार्फत 46,500 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी होगी। यानि इस आम आदमी के बजट में आम आदमी के ऊपर 20,500 करोड़ रूपये का बोझा बढ़ा दिया गया है।

विजय जावंधिया, पूर्व अध्यक्ष,
शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र

यूरोप में ज्ञान संघर्ष

[विद्या आश्रम को हालैंड की एक कान्फ्रेंस में अपने 'ज्ञान सत्याग्रह' के विचार रखने के लिये आमंत्रित किया गया था। अमित बसोले इसीलिए यूरोप गये थे जब उन्होंने इटली, आस्ट्रिया, फ्रांस और हालैंड में सक्रिय छात्र समूहों से विस्तृत औपचारिक और अनौपचारिक वार्तायें कीं।]

हाल की एक यूरोप यात्रा (15 से 25 मार्च, 2010) में हमने विभिन्न यूरोपीय देशों में उच्च शिक्षा के निजीकरण के विरोध में संघर्षरत छात्रों व कार्यकर्ताओं से बात की। नीचे इन संघर्षों और उनमें निहित मुद्दों की एक संक्षिप्त रपट पेश है।

एडू-फैक्टरी (शिक्षा-उद्योग) नाम से विश्वविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो ज्ञान की अर्थव्यवस्था को 'ज्ञान के पूँजीवाद' के नाम से पुकारता है और यह मानता है कि पूँजीवाद के इस चरण में कारखाने का स्थान विश्वविद्यालय ने ले लिया है और यह कि जैसे संघर्ष पहले कारखानों में होते थे वैसे संघर्षों का स्थान अब विश्वविद्यालय बन गया है।

बोलोन्या प्रक्रिया के नाम से सन् 1999 से उच्च शिक्षा में हो रहे सुधारों के खिलाफ पिछले पाँच वर्षों से यूरोप के अधिकांश देशों के छात्र सड़क पर उतर आये हैं। इटली के बोलोन्या शहर में यूरोप का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यहीं 1999 में अनेक यूरोपीय देशों के शिक्षामंत्रियों की बैठक में सुधार की इस प्रक्रिया का फैसला किया गया। इसे छात्र व कार्यकर्ता विश्वविद्यालय का निगमीकरण कहते हैं। रोम, पेरिस और वियना में छात्रों और अस्थाई अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों ने सड़क पर उतरने के अलावा व्याख्यान कक्षों और कार्यालयों पर कब्जा कर लिया और वहाँ से अपनी स्वायत्त गतिविधियों एवं कार्यशालाओं का संचालन किया। वियना के छात्रों द्वारा उनकी प्रसिद्ध कला अकादमी पर कब्जा तीन महीने तक चला जब विश्वविद्यालय प्रशासन अंत में उन्हें खदेड़ निकालने में सफल हुआ।

बोलोन्या प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर विभिन्न यूरोपीय देशों की उच्च शिक्षा में समानता लाकर एक 'यूरोपीय उच्च शिक्षा क्षेत्र' के निर्माण का है। इसमें उद्देश्य यह है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र आसानी से दूसरी जगहों पर जा सकें और पूरे यूरोप में एक समान श्रम बाजार का निर्माण हो। अब जो नये देश यूरोपीय यूनियन में शामिल होंगे उन्हें बोलोन्या प्रक्रिया की शर्तें मानने की बाध्यता है।

जमीन पर बोलोन्या प्रक्रिया का जो अर्थ निकलता है वह यह है कि विश्वविद्यालयों में निजीकरण बढ़ रहा है और मानविकी व समाज विज्ञान के विभागों का वित्तीय अनुदान घट रहा है। उच्च शिक्षा तक की पहुँच कठिन होती जा रही है। कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि प्रतिस्पर्धा, कार्यक्षमता, काबिलियत, छात्र विचरण और यूरोप समरसता जैसे मुहावरों के पीछे बोलोन्या प्रक्रिया का उद्देश्य एक सर्वयूरोपीय शैक्षणिक श्रम बाजार का निर्माण है जो बड़ी बौद्धिक श्रम शक्ति के मार्फत ज्ञान की वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूरोप को प्रतिस्पर्धात्मक बनाये। छात्र और मजदूर के बीच का विभाजन धुँधला होता जा रहा है और बोलोन्या प्रक्रिया का विरोध करने वाले कार्यकर्त्ता कहते हैं कि ये छात्रों के विरोध नये मजदूरों के विरोध हैं।

इटली और ऑस्ट्रिया में हमारी मुलाकात उन छात्रों से हुई जिन्होंने वियेना में हो रहे बोलोन्या प्रक्रिया के दस वर्ष पूरे होने के जश्न के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोधी सम्मेलन संगठित किया था। इस 4 दिवसीय विरोधी सम्मेलन में भाग लेने के लिये इटली, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि से छात्र कार्यकर्त्ता आये थे। पहले दिन एक बहुआयामी 'रास्ता रोको' किया गया जिसमें छात्र शहर में चारों तरफ फैल गये और उन्होंने सारे रास्ते रोक दिये। उनमें तेजी थी, जब तक पुलिस वाले आते वे पहला चौराहा छोड़कर दूसरे चौराहे पर पहुँच जाते थे। विरोध के इन रूपों के साथ ही रचनात्मक कार्यों के रूप में संघर्षकर्त्ताओं ने कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया।

हालाँकि ये सब छात्र विश्वविद्यालयों में किये जा रहे परिवर्तनों का विरोध कर रहे हैं, जिन कार्यकर्त्ताओं से हमने बात की सभी ने यह कहा कि वे विश्वविद्यालय का पुराना रूप नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ 'मरा हुआ ज्ञान' पढ़ाया जाता है। उसके स्थान पर वे ऐसे नये विश्वविद्यालय की बात करते हैं जो स्वायत्त होगा और जहाँ जीवन्त ज्ञान का निर्माण होगा और वहाँ मरे हुये ज्ञान के एकतरफा स्थानांतरण का काम नहीं होगा। वे अपनी खिलाफत को नये विश्वविद्यालय की अपनी दृष्टि से जोड़ते हैं। रोम में जिस छात्र समूह के साथ हम रुके थे उनके पास अपना स्थान है जहाँ वे विचारगोष्ठियाँ करते हैं, फिल्में दिखाते हैं, विदेशी छात्रों को इटली की भाषा पढ़ाते हैं और प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा में कानूनी मदद संगठित करते हैं। इस तरह विश्वविद्यालय के संघर्षों के मार्फत छात्र समाज में आकार ले रहे नये असंगठित मजदूर वर्ग के साथ सक्रिय रिश्ते बना रहे हैं। इन नये संघर्षों की सफलता अथवा असफलता शायद छात्रों और समाज के कामगार वर्गों के इस नये दोस्ताने पर ही निर्भर है।

- अमित बसोले

पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोकविद्याधरों की दखल

इंदौर के वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज के वार्षिक सम्मेलन में इस वर्ष लोकविद्याधरों ने दखल ली और समाज में लोगों के पास जो ज्ञान है, जिसे लोकविद्या कहते है, उसे कॉलेज के ज्ञान के साथ बराबरी में खड़ा करने का प्रयास किया। किसानों और कारीगरों के ज्ञान को समाज में प्रतिष्ठा मिले इस उद्देश्य से किये गये इस प्रयास में कई तरह के कार्यक्रम, प्रदर्शन व गोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस कॉलेज में नियमित छात्रों के अलावा ऐसे आदिवासी छात्र भी पढ़ते हैं जो दिन में कहीं काम करते हैं और शाम को सांध्यकालीन कक्षाओं में पढ़ते है। ऐसे छात्रों के बीच लोकविद्याधरों के इस प्रदर्शन ने और लोकविद्या पर की वार्ताओं ने आत्मविश्वास पैदा किया।

कारीगरों में अंतर सिंह और दरयाव सिंह ने लोहे से संडसी, खुरपी, हथौड़ा आदि औजार बनाकर दिखाये। अपनी छोटी-सी भट्ठी पर उचित तापमान के साथ लोहे में कठोरता कैसे लायी जाती है इसका ज्ञान कारीगरों ने विद्यार्थियों को दिया। सुनील प्रजापति ने मिट्टी के खिलौने, बर्तन एवं आकर्षक शिल्प बनाकर दिखाये। अर्जुन कुमार वर्मा, प्रमोद रायकवार, श्रीमती ज्योति ने चमड़े के खिलौने बनाकर दिखाये। हाथी, घोड़ा, ऊँट, शेर की सुडौलता व जीवंतता दर्शनीय थी। स्त्रियों के एक समूह, जिसमें शान्ता बाई, देवी बाई और अन्य थें, ने सस्ते लेकिन स्वादिष्ट भोजन को बनाकर दिखाया। छगनलाल और रामप्रसाद ने मूर्ति शिल्प की तकनीक का प्रदर्शन किया।

इसी कार्यक्रम में संजय दांगी, गौरव जाकोदिया और सतीश चौहान ने शिक्षा से सम्बन्धित विषय पर विद्या वार्ता का संचालन किया जिसमें निम्नलिखित विषयों पर वार्ता हुई।

- छात्रों की फीस का शिक्षण संस्थानों में होता सदुपयोग और दुरूपयोग।
- इक्कीसवीं सदी में शिक्षा पद्धति कैसी हो?
- शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धन में छात्रों की भागीदारी कैसे हो?
- शैक्षणिक काल में छात्र 'सूचना के अधिकार' का उपयोग क्यों नही करते ?

एक आकर्षक कार्यक्रम लोकस्थ खेलों का भी रखा गया जिसमें 'हिंगोट युद्ध' जैसे लोकस्थ खेलों पर विस्तृत चर्चा हुई।

सबसे आकर्षक आयोजन 'ज्ञान की प्रदर्शनी' का था जिसमें सन् 1600 से 2010 तक चार सौ वर्षों में ज्ञान की दुनिया में आये बदलावों को पोस्टर्स के मार्फत दिखलाया गया था।

इसी दौरान छात्रों ने पहल लेकर संस्थान में कई वर्षों से बंद पड़ी मशीनों की मरम्मत कर उन्हें चालू करने का कार्य भी कर दिखाया।

तेलंगाना के साथ जुड़ी संभावनायें

विद्या आश्रम की ओर से डा. बी. कृष्णराजुलु नायडू द्वारा श्रीकृष्ण आयोग को प्रेषित पत्र का एक हिस्सा

तेलंगाना की वर्तमान माँग अबकी बार ऐसे राष्ट्रीय और वैश्विक सन्दर्भ में उभरकर आई है जो पहले के अवसरों की तुलना में काफी अलग है। हालाँकि तेलंगाना की अलग राज्य की माँग तो वही है लेकिन पहले की अवसरों की तुलना में पुनर्रचना और विकास के मौके काफी अलग हैं। दो दशकों से यह दुनिया और उसके साथ यह राष्ट्र एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो एकदम नया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान के नाम पर होने वाले उपक्रम उत्पादन, सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिये ये तय कर रहे हैं, अत: किसी भी नये राज्य के लिये आजादी के बाद से आगे बढ़े हुये राज्यों में जो विकास नीति अपनाई गई उसी का अनुसरण करना जरूरी नहीं रह गया है।

लोकविद्या और संचार प्रौद्योगिकी के बीच ऐसे सकारात्मक रिश्ते बनाये जा सकते हैं जो विकास का एक नया रास्ता उजागर करें और नये राज्य पूँजीवादी औद्योगिक और शैक्षणिक विकास के कष्ट और शोषण भरे रास्तों से अलग रास्ता चुनें। ऐसा करने में यह अवश्य जरूरी होगा कि अर्थ और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्राथमिकतायें बदली जायें। ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक बच्चों की भाषा, कला और सम्प्रेषण की क्षमताओं को बखूबी समझते हैं। ये क्षमतायें साइंस और गणित के पाठ्यक्रमों के बोझ से दब जाती हैं। ज्ञान आधारित नये विचारों और उपक्रम के अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा को इस तरह पुनर्गठित किया जा सकता है कि ग्रामीण बच्चों और नौजवानों की ऊर्जा और पहल खुलकर सामने आये। इसी में सच्चे आर्थिक और सामाजिक स्वराज्य प्राप्त करने का पुख़्ता आधार हो सकता है।

हैदराबाद तेलंगाना को आगे खींचे इसकी ज़रूरत नहीं है। नये तेलंगाना में हैदराबाद की सेवाओं से ऐसे संचार के तरीके विकसित किये जा सकते हैं जो नई आर्थिक गतिविधियों, बाजार के नये रूपों, प्रशासन के नये तरीकों और प्रबन्धन के नये आदर्शों के लिये ज्ञान के विभिन्न स्थानों और रूपों के बीच सहभागिता और पारस्परिक समझ के रिश्ते कायम करें। तेलंगाना के लोगों ने अद्भुत पहल और क्षमता के साथ बहुत कठिन परिस्थितियों में बड़े-बड़े संघर्ष संगठित किये हैं। यह क्षमता जब लोकविद्या के साथ समायोजित हो जायेगी तो एकदम नये किस्म की पुनर्रचना और विकास की उम्मीद की जायेगी। इस बात की अवश्य ज़रूरत होगी कि सरकार लोकविद्या अनुसंधान पर खर्च करे। यह अनुसंधान खेतों और छोटे-छोटे कारखानों में होगा जो लोकविद्या में एक गति, एक नई उम्मीद और एक नई दिशा का संचार करेगा जिससे लोकविद्या परिवार, गाँव, जाति, समुदाय और क्षेत्र की प्रतिरक्षात्मक सीमाओं को लाँघ सके। यह सब हो इसकी उम्मीद एक छोटे राज्य में की जा सकती है। वह एक ऐसा राज्य होना होगा जो लोगों के नजदीक हो और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो। अगर नया तेलंगाना राज्य बनता है तो यह उसकी दृष्टि का हिस्सा हो सकता है।

अनगढ़-मनगढ़

हम त केहू के ना मानित

मैं कई साल बाद बनारस वापस आया था। बस बालिग होते होते ही यहाँ से चला गया था, इसलिए यहाँ की कोई दार्शनिक याददाश्त नही थी। अब दर्शन पढ़कर आया, तो जहाँ दर्शन न हो वहाँ भी दिखाई देता था। थोड़ा बहुत तर्क देना भी सीख आया था, सो दोस्त लोग चाहे ना मानें, कई बार जवाब नही दे पाते थे।

हम लोग शहर में घूम रहे थे और बुलानाले के इलाके में एक जगह चाय पीने बैठ गये। कुछ ट्रैफिक कंट्रोल था, इधर से जाइये, उधर से मत जाइये, वगैरह। हमने बगल में बैठे आदमी से पूछा

''क्या बात है? टहरेहू न दी हैं का?''

वह बोला ''चीफ जस्टिस आफ इंडिया आयल हौव्वें। बाबा (विश्वनाथ) के दरसन बदे। एही से कुल नाकाबंदी हौ।''

इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसके बगल में बैठा आदमी बोल उठा ''होइहैं कौनो, हम त बाबा के मानिला और केहू के ना मानित।''

मैं इस वक्तव्य की दार्शनिक गहराई में उतर ही रहा था कि चाय वाला गद्‌गद् होकर हंस पड़ा। बोला

''एही से त हम एन्हें पसंद करीला, जब बोललन तब एकदम असली बात!''

पहले आदमी ने पूछा ''औघड़ हौव्वें की का?''

दुकान वाला बोला ''ना ही, सब जने एन्हें अनगढ़ कहलन।''

जब मैं पी.एच.डी. कर रहा था, तब पी.जी. होस्टल की कैंटीन ने यह ख्याति अर्जित की थी कि यहाँ अक्सर कांट और मार्क्स पर चर्चायें सुनाई देती हैं। लड़के गर्व करते थे कि ऐसी जबर्दस्त जगह पर हम रहते हैं। दार्शनिक विषयों की चर्चाओं के बारे में मेरे दोस्त एक किस्सा सुनाया करते थे, कहते थे ''शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने मिथिला गये तो गाँव के बाहर कुएँ पर पानी भरती एक स्त्री से उन्होंने मिश्राजी का घर पूछा। जानते हैं स्त्री ने क्या उत्तर दिया? उसने घर का रास्ता बताया और कहा कि उस गली में जिस घर के बाहर तोते यह बहस कर रहे हों कि सत्य ज्ञान का अंतर्निहित गुण है या बाह्य गुण है, वही घर मिश्राजी का है।''

इस क्षेत्र के लोगों की दार्शन रूचि और दर्शन क्षमता के उदाहरणों की कोई कमी नही है। लेकिन आज चाय की दुकान पर का सामना शंकराचार्य, मंडन मिश्र, याज्ञवल्क्य, कांट या मार्क्स का सामना करने जैसा नही था। बड़ी से बड़ी सत्ता को नकारने का बुनियादी विचार सामान्य लोगों में कौन-सी गलियों से चल कर आता है? मिट्टी में दर्शन हो तो उसकी गंध सामान्य लोगों की वाणी से आती है।

याद करता हूँ तो लगता है कि मेरे लिए वह एक निर्णयात्मक एनकाउंटर था। दर्शन कहाँ होता है इससे परिचय की शुरूआत हुई। किसी बुनियादी परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार ऐसे विचारों में खोजा जाये तो कैसा रहेगा?

- बुधराम

जौनपुर जिले में किसानों की समस्याएँ, संगठन और संघर्ष

राजनाथ यादव

जौनपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को लेकर लम्बे समय से ही किसानों को संगठित करके संघर्ष करता रहा है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजनाथ सिंह यादव के नेतृत्व में किसानों ने निम्नलिखित मुद्दों को लेकर संघर्ष किया है।

1. बिजली की समस्या और संघर्ष– बिजली की समस्या किसानों की प्रमुख समस्या रही है, जिसमें किसानों को सुबह-शाम कभी भी बिजली नही मिलती थी। भा0कि0यू0 जौनपुर इकाई ने किसानों को संगठित करके बिजली की समस्या पर निम्नलिखित माँगो को लेकर संघर्ष चलाया—

i) बिजली की वितरण व्यवस्था बदली जाय और किसानों को सुबह-शाम बिजली दी जाय।
ii) किसानों का बिजली विद्युत भार शुल्क समाप्त किया जाय।
iii) बिजली बिल बकायेदार किसानों का कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न न किया जाय।
iv) बिजली की बकाया धनराशि न जमा करने पर किसी भी किसान की न तो आर0 सी0 काटी जाय और न ही उसे जेल भेजा जाय।

इन सभी माँगों को लेकर शाहगंज तहसील पर 7 दिनों तक किसानों ने धरना दिया और किसानों को बिजली के सवाल पर काफी राहत मिली। अभी हाल ही में 2-3 फरवरी 2010 को जंघई में किसानों ने बिजली वितरण व्यवस्था को लेकर चक्का जाम किया।

2. सिंचाई की समस्या और संघर्ष– नहर में समय से पानी उपलब्ध हो, जायद की फसल का कर न लिया जाय, वर्ष में दो बार माइनरों की सफाई करायी जाय, किसानों से सिंचाई शुल्क जबरदस्ती या प्रशासन के बल पर न लिया जाय, इन सभी माँगों को लेकर किसानों ने भा0कि0यू0 के नेतृत्व में धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम किया। जायद की फसल का कर यूनियन ने संघर्ष से माफ करा लिया है, किसानों को जायद की फसल का कर नही देना पड़ता है।

3. धान और गेहूँ क्रय केन्द्रों के लिए संघर्ष– न्याय पंचायत स्तर पर क्रय केन्द्र बने, क्रय केन्द्रों पर ही किसानों के अनाजों का भुगतान हो जाय, अनाजों की बिक्री दिन में हो इसके लिये यूनियन ने संघर्ष के बल पर क्रय केन्द्रों की व्यवस्था ठीक कराई है। यह व्यवस्था आगे भी ठीक रहे इसके लिए भा0कि0यू0 का सदस्य क्रय के समय प्रत्येक क्रय-केन्द्र पर उपस्थित रहते हैं।

3) खाद व बीज के लिए संघर्ष– भा0कि0यू0 किसानों को खाद व बीज सरकारी दुकानों से ही समय-समय पर मिले इसके लिए सरकारी दुकानों पर पुलिस को न लगाकर भा0कि0यू0 के सदस्यों को लगाया जाय इसके लिए संघर्ष करता है।

4) सरकारी राशन की दुकान से वितरण व्यवस्था– दुकानों पर वितरण व्यवस्था में अनियमितता को लेकर भा0कि0यू0ने 26-6-2009 को जिला मुख्यालय जौनपुर पर धरना दिया। यूनियन की तरफ से ये माँग रखी गई कि दुकानों पर राशन, तेल तथा अन्य वस्तुएँ हर महीने समय से उपलब्ध करायी जाय, बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय कार्ड पात्र लोगों को दिया जाय अपात्र लोगों का कार्ड निरस्त किया जाय। वितरण व्यवस्थाओं में जब भी गड़बड़ी होती है भा0कि0यू0 के कार्यकर्ता शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करके सुधार लाते है।

5) स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या और संघर्ष– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बादशाहपुर 3-7-2009 को भा0कि0यू0 ने किसानों की समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य केन्द्र का घेराव किया जिसमें प्रमुख माँगे रखी गई- (I) स्वास्थ्य केन्द्रों से ही दवा देने की व्यवस्था की जाय। (II) मरीजों को दवा बाहर से लेने के लिए परची न बनाई जाय। (छ) प्रसव के समय लाभार्थी से जबरदस्ती वसूली बन्द की जाय। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता अभियान योजना के तहत प्रत्येक गाँव में ब्लीचिंग पावडर का छिड़काव किया जाय। भा0कि0यू0 द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को लेकर समय-समय पर संघर्ष चलाया जाता है।

6) किसान वृद्धा मासिक पेंशन दिया जाय– किसानों को वृद्धा मासिक पेंशन दिया जाय इसके लिए भा0कि0यू0 ने सैकड़ों किसानों के साथ जिला मुख्यालय पर धरना दिया। जिला अध्यक्ष का कहना है कि किसान अपने ज्ञान व मेहनत के बल पर सबकी जिन्दगी चलाता है, 60 वर्ष के बाद वह मेहनत करने के लायक नही रह पाता है इसलिए किसानों को 1500/- रूपये पेंशन दी जानी चाहिए।

7) जमीन के पट्टे को लेकर संघर्ष– जिन गरीबों को जमीन का पट्टा कराया गया है उस जमीन पर उनका तत्काल कब्जा कराया जाय तथा भू- माफियाओं द्वारा, गाँव समाज की जमीन पर से अवैध कब्जा, अतिक्रमण हटाया जाय। इसको लेकर भा0कि0यू0 ने चक्का जाम किया है। यूनियन की यह माँग रही है कि 2 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों को बिजली, पानी मुफ्त किया जाय।

8) पुलिस प्रशासन के खिलाफ संघर्ष– पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी भा0कि0यू0ने कई बार संघर्ष चलाया है, F.I.R. के नाम पर अवैध वसूली चौकी एवं थानों पर की जाती है। इस बात को लेकर जंघई चौकी तथा मीरगंज थाना को घेरा गया है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि पुलिस किसानों को फर्जी मुकदमों में फँसाती है। किसानों की शिकायत भी थानों पर बिना पैसा लिए दर्ज नही होती है।

9) मनरेगा के सवाल पर संघर्ष– मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों को कम से कम 200 दिन का काम दिया जाय। काम उपलब्ध न होने पर पूरी मजदूरी दी जाय। इस सन्दर्भ में शासन प्रशासन को पत्रक भेजकर तथा धरना-प्रदर्शन करके संघर्ष चलाया गया। किसानों और मजदूरों को बुनियादी सुविधायें मिलें इसके लिए भी संघर्ष जारी है।

10) शिक्षा नीति बदले– देश की दोहरी शिक्षा नीति के खिलाफ भी भा0कि0यू0 समय-समय पर आन्दोलन चलाता रहा है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि पूरे देश में एक समान शिक्षा लागू की जाय, किसानों के बच्चों को भी कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जाय अर्थात उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी हो, शिक्षा, चिकित्सा मुफ्त की जाय। पूरे देश में पाठ्यक्रम समान होने चाहिए, भाषायें विभिन्न हो सकती है। शिक्षा, सस्ती और समान होने से सभी लोग शिक्षित हो पायेंगे तभी समाज व राष्ट्र का विकास होगा।

11) विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ संघर्ष– 5 जुलाई 2008 को जिला मुख्यालय जौनपुर पर हजारों किसानों ने भा0कि0यू0 के नेतृत्व में विश्व व्यापार संगठन की शर्तो को भारत में न लागू किया जाय इस बात को लेकर आन्दोलन चलाया क्योंकि W.T.O. की शर्ते लागू होने से गरीब किसान खेती नही कर पायेंगे और अपनी जमीन बेचने पर विवश हो जायेंगे। शर्ते लागू होने पर कोई भी किसान अपनी इच्छानुसार खेती नही कर पायेगा। सभी किसानों पर कानूनी बंधन लग जायेगा।

अन्त में जिलाअध्यक्ष राजनाथ सिंह यादव ने बताया कि हमारे देश में राष्ट्रीय किसान विकास परिषद का गठन किया जाय तथा उसका अध्यक्ष चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैट को बनाया जाय। इसकी माँग भा0कि0यू0 जौनपुर राज्य व केन्द्र सरकार से लगातार कई वर्षो से पत्रक के माध्यम से करता रहा है।

राजनाथ यादव
भा0कि0यू0 जिला अध्यक्ष, जौनपुर
मो0-9454794131
वार्ता के आधार पर

उड़ीसा में टाटा की सरकार

उड़ीसा में भी आदिवासियों के लोकतांत्रिक आंदोलन को खत्म करने के लिए कलिंग नगर जिले में टाटा के समर्थन से एक ग्रीनहंट हमला जारी है। मार्च 2010 के अन्तिम दिनों में शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने वाले संगनों द्वारा जारी निम्नलिखित पर्चे में यह बात सफाई से लिखी गई है।

दबर कलुन्दिया विस्थापन विरोधी जनमंच के आदिवासी नेता हैं। जयपुर जिले के जिलाधिकारी ने इन्हें वादा किया था कि 28 मार्च को वे बालीगोथा गांव आयेंगे और ग्रामीणों के कष्ट सुनकर उसका समाधान करेंगे। लेकिन एक ही दिन में जिलाधिकारी ने अपना वादा तोड़ दिया और आदिवासियों के लोकतांत्रिक व अहिंसक आंदोलन को दबाने के लिए सशस्त्र पुलिस की 24 प्लाटून वहाँ पर भेज दिये। बड़े पैमाने पर खून-खराबे का डर है गाँव वाले बहुत भयभीत हैं। याद रहे 2 जनवरी 2006 को पुलिस की गोलाबारी में 14 आदिवासी पुरूष, स्त्री और बच्चे मारे गये थे।

अब 3 महीने से विरोध करने वाले कलिंग नगर के गाँवों पर पुलिस छाई है आौर गाँव से बाहर निकलने पर दर्जनों गिरफ्तार किये जा चुके है। झूटे मुकदमें दाखिल किये गये हैं। पुलिस वाले और टाटा के गुण्डे विस्थापन विरोधी जन मंच के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए बार-बार देर रात हमले करते हैं। ठेके के हत्यारे आदिवासी नेताओं के लिए लाये गये हैं बाली गोथा गाँव के अमीन बनरा की मृत्यु इसी तरह हुई। अब गाँव के अन्दर से रास्ता बनाने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस लगाई गई है। विरोध दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन के हर तरीके का मुकाबला शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीकों से किया गया है। विस्थापन विरोधी जन मंच ने कई बार यह साफ किया है कि न तो उन्हें माओवादियों का समर्थन प्राप्त है और न वे किसी किस्म की हिंसा ही चाहते हैं। मंच ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उन्हें विस्थापन और पागलों जैसा औद्योगिकरण कत्तई मान्य नहीं है। इनके चलते इलाके में बड़े पैमाने पर प्रदूषण हुआ है जिसके नतीजे स्वरूप बिमारी और फसल बर्बादी का आलम सभी ओर नज़र आता है।

अचरज की बात यह है कि अख़बार और टी0वी0 दोनों में ही कलिंग नगर के घटनाक्रम को कोई स्थान नही दिया जा रहा। मुख्य धारा के राजनीतिक दल भी आपस में और शासन करने वाले दल के साथ सहमत नज़र आते हैं। इसके चलते यहाँ के सभी नागरिक बहुत चिंतित हैं और टाटा कारखाने के लिए विस्थापन का विरोध कर रहे गाँवों में पुलिस भेजने का नतीजा क्या होगा यह समझ रहे हैं।

हम यह माँग करते हैं कि सरकार टाटा इस्पात कम्पनी के किराये के टट्टू का काम न करे और उस क्षेत्र से पुलिस को तुरंत वापस बुलायें वरना यदि खून-खराबा हुआ तो सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट भी रोक देना चाहिए क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में यह रास्ता कृषि योग्य भूमि और आदिवासियों की सामुदायिक जमीनों पर ही बनना है। सरकार द्वारा 14 आदिवासियों के बलिदान का सम्मान करते हुए टाटा प्रोजेक्ट को तुरंत बन्द कर देना चाहिए। आदिवासियों की उनकी जमीनों से विस्थापन और बेदखली तुरंत बंद होनी चाहिये। सरकार की यह तुरंत की जिम्मेदारी है कि आदिवासियों को आश्वस्त करें कि पुलिस या टाटा के गुण्डे उन पर हमले नहीं करेंगे और इलाके में शांति कायम करें। इन गाँवों में स्वास्थ्य रक्षा के समूह तुरंत भेजे जाने चाहिए क्योंकि कई दिनों से लोग गिरफ्तारी के डर से डाक्टर के पास भी नहीं जा सके हैं।

हम सभी नागरिकों, प्रगतिशील समूहों और मीडिया के व्यक्तियों से अपील करने हैं कि वे सरकार के फ्रांसीवादी प्रवृत्ति के खिलाफ अपनी आवाज उटायें और कलिंग नगर के आदिवासियों के साथ एकता का प्रदर्शन करें।

प्रफुल्ल समन्तारा, लोकशक्ति अभियान
लिंगराज, समाजवादी जन परिषद
राधाकांत सेटी, भाकपा-माले लिबरेशन
प्रशांत पाइकराय, पी०पी०एस०एस०
भालचन्द्र षड़ंगी, भाकपा-माले न्यू डेमोक्रेसी
लिंगराज आजाद, एन०एस०एस०

विद्या आश्रम पर किसान चिंतन

17 अप्रैल 2010 को विद्या आश्रम सारनाथ में भारतीय किसान यूनियन के इस क्षेत्र के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। वाराणसी, मिर्जापुर, चन्दौली और गाजीपुर के सभी पदाधिकारी उपस्थित थें। करीब 4 घण्टे चली इस वार्ता में किसानों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा हुई और यह आपसी सहमति बनी कि किसानों द्वारा अपने संघर्ष और आंदोलन को अगले स्तर पर उठाये बगैर कोई भी स्थाई हल संभव नही है। अपनी जमीन बचाने के लिए, कृषि उत्पादन के दाम के लिए, बिजली, पानी, खाद, सभी के लिए किसान को सतत संघर्ष करना पड़ता है और दूसरी तरफ उसकी आर्थिक हालत में बराबर गिरावट आती जा रही है। यह भी बात हुई कि जब तक किसान किसी भी शहरवासी या पढ़े–लिखे व्यक्ति के बराबर का नागरिक होने का दावा नहीं पेश करता तब तक उसके श्रम और विद्या की लूट जारी रहेगी। किसानों की जमीन का अधिग्रहण और बिजली के सवाल बैठक पर छाये रहें। प्रदेश महासचिव श्री राजेन्द्र शास्त्री ने बैठक के समापन के समय निम्नलिखित चार मुद्दों को चर्चा के निष्कर्ष के रूप में पेश किया।

1. राष्ट्रीय संसाधनों का गाँव और शहर के बीच बराबर का बँटवारा हो, इसमें बिजली और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। सबको बराबर बिजली मिले और सबके बच्चों को समान शिक्षा के अवसर मिले।
2. किसानों की भूमि का अधिग्रहण बंद हो। जहाँ समझौता हो जाय वहाँ मुआवजा पेशगी दिया जाय।
3. हर किसान को 60 वर्ष की आयु के बाद रू.1500/-प्रति माह पेन्शन दी जाय। इसमें जमीन आदि के आधार पर कोई फर्क न किया जाय।
4. कृषि उत्पादन गेहूँ, आलू, इत्यादि के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी यूनियन की राज्यस्तरीय माँग आगे बढ़ाई जाय।

बैठक में शास्त्री जी के अलावा वाराणसी मण्डल अध्यक्ष–जगदीश सिंह यादव, मिर्जापुर मण्डल अध्यक्ष–प्रहलाद सिंह, प्रदेश सचिव– सिद्धनाथ सिंह, वाराणसी जिला अध्यक्ष– लक्ष्मण प्रसाद, मिर्जापुर जिला अध्यक्ष– अली जमीर खान, चन्दौली जिला अध्यक्ष–गजानन्द सिंह, गाजीपुर जिला अध्यक्ष–दिनेश पाण्डेय और विद्या आश्रम के सुनील सहस्त्रबुद्धे, दिलीप कुमार और विनोद चौबे ने विशेष रूप से अपने विचार रखे।

ऐसा क्यों है?

मै समझ नही पा रही हूँ कि ऐसा क्यों है? संगीत के क्षेत्र में लोक संगीत को समाज में इज्जत है। समारोह और सम्मेलनों में लोग इसे सराहते हैं, पसंद करते हैं। सिनेमा संगीत में इसकी लोकप्रियता का जवाब नही है। नौशाद, सचिनदेव बर्मन, ओ.पी. नैय्यर ने तो लोक संगीत के बल पर लोकप्रियता के झंडे गाड़ दिए हैं। नए संगीतकारों में रहमान, भारद्वाज आदि भी इस में पीछे नही हैं। बोलों (गीत) के मामले में तो गीतकारों ने लोकगीत ही उठा लिये हैं। लोकगायकी का लोहा कौन नहीं मानता? ठुमरी, चैती, होरी, कहरवा, निर्गुण सभी ने शास्त्रीय संगीत में अपनी खास जगह बना ली है। नाटकों में भी लोककथा, लोकवाद्य, और लोकजीवन को इज्जत का स्थान है। हबीब तनवीर को कौन नहीं जानता? कविता, कहानी, उपन्यास, और पटकथाओं में लोकभाषाओं का प्रचूरता से इस्तेमाल हो रहा है और लोग इनके दम-खम और अभिव्यक्ति की समृद्धता के कायल हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने हिन्दी साहित्य में जो रास्ता खोला वह आज बहुत चौड़ा हो चुका है। और उस पर चलने वाले साहित्यकारों की एक बड़ी संख्या है और वे लोकप्रिय भी हैं। शिल्प की दुनिया में लोककला का सानी नही है। फैशन की दुनिया में लोकशिल्प को ऊँचा मान है। कपड़े की बुनाई, रंगाई, छपाई, कसीदाकारी, फर्नीचर के डिजाईन, घरों की सजावट और बनावट, सब में लोककला की बड़ी इज्जत है।

साइंस और टेक्नोलॉजी वाले न जाने किस हीन भाव से पीड़ित हैं? जब कला की दुनिया सार्वजनिक तौर पर लोककला (यानि कला क्षेत्र का लोक ज्ञान) को प्रतिष्ठा दे रही है तो साइंस/टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह क्यों नही हो पा रहा है? एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट किसान के ज्ञान को कोई तवज्जो नही देता, टेक्सटाइल इंजिनियर बुनकर को गंवार समझता है। मिट्टी, लोहा, लकड़ी, धातु-अधातु, प्लास्टिक से तमाम तरह की चीजें बनाने वाले कारीगर इन इंजिनियरों की नज़र में महज मजदूर हैं। साइंस/टेक्नोलॉजी के पढ़े लोगों की नज़रों में पहाड़, नदी और जंगलों में रहने वाले लोग महज प्राणी (जंगली) हैं! लोक के साथ ज्ञान का लेन-देन करने में न जाने क्यों ये साइंटिस्ट खुद को अपमानित समझते हैं? क्या ये अंहकार है? या कोई और बात है?

यह सच है की डेवेलपमेंट सेक्टर एन.जी.ओ. के मार्फत बड़ी ऊँची आवाज में साइंस/टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोकज्ञान की वकालत कर रहा है। इनके कामों में गरीबी हटाने से लेकर तो पर्यावरण, प्रदुषण, स्वास्थ्य-रक्षा, सब समस्याओं में लोकज्ञान और लोकतकनीक एक हल के रूप में सामने लाये जाते हैं। लेकिन इसमें दम नही है, क्योंकि एक तो इन संस्थाओं की भूमिका ही अलग है और दूसरा, ये साइंस/टेक्नोलॉजी वाले लोग ही नही हैं। इनके कहने से क्या होगा?

यह सोचते समय इस बात पर ध्यान गया की कला क्षेत्र में संगठित विद्या (शास्त्रीय ज्ञान) और लोकविद्या में सतत एक रिश्ता रहा है, आपस में लेन-देन रहा है, एक दूसरे में सम्मिलित औार समाहित होने की क्रियाएं होती रही हैं। दर्शन क्षेत्र के जानकार हमें बताते हैं कि हमारे समाज में लोक और शास्त्र के बीच उल्टा रिश्ता नही रहा है बल्कि लोक प्रचलन को एक आधारभूत कसौटी की मान्यता मिलती रही है। कुछ वर्षो पूर्व हिन्दी साहित्यकारों ने नामवर सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर लोक और शास्त्र के बीच रिश्ते पर एक व्यापक बहस चलायी थी। अभी हाल ही में संगीत के क्षेत्र में 'देशी' और 'मार्गी' की अवधारणाओं के मार्फत लोक और शास्त्र के बीच के रिश्तों को जानने का मौका मिला। कपिला वात्स्यायन के एक लेख के अनुसार 'देशी' और 'मार्गी' में ऊँच-नीच का रिश्ता नही रहा है। बराबरी का रिश्ता रहा है। यह क्या था? कला मर्मज्ञ निहार रंजन राय के लेखन में भी यही बात उजागर होती है। तो क्या बात है कि साइंस/टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई विचार नही हो पा रहा है?

हमारे यहाँ साइंस/टेक्नोलॉजी की पढ़ाई विश्वविद्यालयों के साथ आई है और शुरू से ही इसने पूँजीवादी व्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाया है। भारत जैसे समाजों में साइंस/टेक्नोलॉजी का ज्ञान शुरू से ही एक संगठित ज्ञान के रूप में सामने आया। एक ऐसे संगठित (शास्त्रीय) ज्ञान के रूप में, जो लोकज्ञान की जान लेकर ही अपना साम्राज्य स्थापित करता है। शायद शास्त्रीय ज्ञान और लोकज्ञान के बीच इस तरह के उल्टे रिश्ते की शुरूआत साइंस ने ही की हो और उसी के चलते साइंस/टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का रूख लोकज्ञान के प्रति मैत्री का नही बन पा रहा हो। चूँकि हमारी शिक्षा का मूल्य साइंस आधारित रहा है इसलिये ज्ञान की अन्य धाराओं में भी, कला और मानविकी में भी,यह मूल्य घुसपैठ कर चुका है। विश्वविद्यालय की भूमिका ही लोकज्ञान के विरोध की बन गई।

यह भी देखने को मिलता है कि कला, पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की डिग्री को बहुत तवज्जो आज भी नहीं दी जाती। सिनेमा और नाट्य में तो अनेक कलाकारों के उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने संगठित शिक्षा हासिल ही नही की और बुलंदियों तक पहुँचे। अधिकांश कलाकार विश्वविद्यालय के बाहर ही रहे हैं, समाज के बीच से सीख कर आए हैं। मनोरंजन की दुनिया में, जो आज एक फलता-फूलता क्षेत्र है, यह बात आम देखी जाती है। आन्दोलनों और जन संघर्षों में ऐसे उदाहरण हमेशा मिलते हैं जब कुशल नेतृत्व करने वाले संगठित विद्या के बाहर से होते हैं। सॉफ्टवेयर का क्षेत्र भी अब इसमें शामिल हो चुका है। ये सभी क्षेत्र विश्वविद्यालय के संगठित ज्ञान पर एकाधिकार को नहीं मानते। इन क्षेत्रों में काबिल लोगों की खोज के लिए डिग्री का सहारा अक्सर बेअसर साबित होता है। ऐसे में साइंस और टेक्नोलॉजी के जानकार कहाँ अटक गये हैं? वे क्यों कूपमंडूक बने हुए हैं?

भारत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। क्या यह अपने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से के ज्ञान भंडार को नजरअंदाज कर के यह लक्ष्य हासिल कर पायेगा? और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह लक्ष्य और इसे प्राप्त करने का रास्ता समाज में और भी गैरबराबरी पैदा नही करेगा?

चित्रा सहस्त्रबुद्धे

पापी बारिश : एक सिनेमा

हाल ही में किसान के जीवन संघर्ष पर एक मराठी सिनेमा 'गाभ्रीचा पाउस' बना है। यह सिनेमा महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के किसानों के जीवन-संघर्ष का एक सहज और संवेदनशील चित्र सामने लाता है।

'गाभ्रीचा पाउस' यानि पापी बारिश। किसना एक सामान्य किसान है जो अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और सात साल के बेटे के साथ रहता है। गाँव में एक किसान की आत्महत्या से ही सिनेमा शुरू होता है। मौत का यह खौफ पूरे परिवार पर शुरू से अंत तक छाया हुआ है। किसना के परिवार की जिन्दगी खेती पर निर्भर है। कपास की खेती है। बुवाई कर्ज लेकर होती है और खेती वर्षा के पानी के आसरे। बादलों का इंतजार है... बादल नही आते, प्राण कंठ तक आ चुके हैं। मायूसी का आलम है। बुवाई का समय टला जा रहा है, क्या करें? माँ और पत्नी को डर है, कहीं किसना कुछ कर न ले। दोनों दिन-रात उस पर नजर रखे हुये हैं और बच्चे को हरदम किसना के साथ कर देती हैं, उसे अकेला नही छोड़ती। किसना उन दोनो के खौफ से अनजान है और हिम्मत बाँधकर खेती करने की ठान रहा है। कुछ बारिश होती है और पत्नी अपने गहने बेचकर बीज लाने का आग्रह रखती है। नये बीज बोये जाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में इतनी बारिश होती है कि खेत डूब जाता है और आधे से ज्यादा पौधे सड़ जाते हैं। परिवार फिर खौफ के साये में। कहीं किसना कुछ कर न ले। किसना उनके खौफ से अनजान बचे-खुचे पौधों को जिलाने में लगता है। किसी तरह फसल होती है और व्यापारी घर से सारी कपास उठा ले जाता है क्योंकि कर्जे का भुगतान कैसे होगा? किसना हिम्मत नही हारता। फिर कर्ज लेता है, कुँयें को गहरा बना कर पानी खींचने का पम्प लगाता है। लेकिन बिजली नदारद है। क्या करें? गाँव का एक साथी उसकी हिम्मत को देखकर कहता है कि हाइटेंशन तार से काँटा डालकर बिजली खींच लो। इसी कोशिश में करंट लगने से किसना की मौत हो जाती है। यही तो होना था, जिसके खौफ ने परिवार को डस लिया था।

पापी बारिश! बैंक से कर्ज के रूप में किसानों के लिये धन की बारिश, पापी बारिश। कपास के किसानों की बलि लेने वाली पापी बारिश!

जमींदारी गई, देश आजाद हुआ लेकिन किसान की हालत बिगड़ती ही गई। किसानों के नाम पर जो भी नीतियाँ बनीं उनसे चुटकी भर किसानों को कुछ मिला लेकिन बड़ा फायदा तो उद्योगपति, व्यापारी और राजनेता ही उठा ले गयें। इसके बावजूद गाँव का बड़ा लुभावना चित्र रंगा जाता रहा है- हरे-भरे खेत, नदी का किनारा, पेड़ों की घनी छाँह, लिपे-पुते घर, हँसते-गाते लोग, कभी रंग-बिरंगे कपड़ों में नाचते लोग...वगैरे। गाँव के लोगों को यह अटपटा सा लगता है क्योंकि गाँव के ज्यादातर लोगों का जीवन अनिश्चितताओं

से भरा है, निरंतर कर्ज पर आधारित गृहस्थी और चिकित्सा व शिक्षा प्राप्त करने में बरबाद होते जा रहे घर। उनकी थाली का खाना कम और रूखा होता जा रहा है। बावजूद इसके अखबार, टी.वी. और सिनेमा में किसान के सुख: दुख को कोई जगह नही है और अगर है भी तो झूठी। गाँव के लोगों की चाहत, पहल, मानस और संघर्ष को कोई अभिव्यक्ति नही है। देश की औद्योगिक प्रगति के लिए किसान-समाज की बलि चढ़ा दी गई यह प्रखर सच है, बावजूद इसके उसने हार नही मानी और अपनी विद्या के बल पर डटा रहा। उसकी इस जीवटता की ताकत से आज का शासक वर्ग एक बार फिर उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी में है। वैश्वीकरण और बड़ी कम्पनियों के हित में वे किसान समाज को तबाह करने में नही हिचक रहे। पापी बारिश की यही पृष्ठभूमि है।

यह सिनेमा सूचना युग में जी रहे किसान समाज पर एक दस्तावेज है। सिनेमा की खासियत है उसकी सहजता और डर के साये में माँ और पत्नी की लगातार वे कोशिशें जो किसना को अकेला नही रहने देतीं, मायूस नही होने देतीं। इन कोशिशों में पैदा होते छोटे-छोटे हास्य प्रसंग और फिर हादसे की आहट से चौकन्ने औरतों के चेहरे! घटनाओं का सही संयोजन, परिवार के अंदर के सहज आत्मीय सम्बन्ध और किसान की लूट के तंत्रों का धीरे-धीरे खुलता जाना एक अच्छी और गंभीर मुद्दे पर बनी फिल्म के लायक ही है। निर्देशन, संगीत, गीत, फोटोग्राफी, अभिनय, विदर्भ की भाषा, संवाद सब अच्छा है।

कविता

हम गुजर गये
कारीगरों की गलियों से
नज़रें चुराकर,दामन बचाकर
खून बहता रहा
दोनों तरफ की नालियों में...

घबराकर गाँवों की तरफ दौड़ पड़े
ताजी हवा,पहाड़,नदी,खुले आकाश से
नज़र उतरी धरती की हरियाली पर
और....
और, साँस जहाँ की तहाँ अटक गई
यहाँ तो लाशें खुद को ढ़ो रही हैं...

-कस्तूरी

लोकविद्या पंचायत, मासिक समाचार पत्र, विद्या आश्रम (सा 10/82 ए, अशोक मार्ग, सारनाथ, वाराणसी-221007) की ओर से **डा.चित्रा सहस्त्रबुद्धे** द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित।
website : vidyaashram.org **Blog :** lokavidyapanchayat.blogspot.com **e-mail :** vidyaashram@gmail.com
प्रेस : **सत्तनाम प्रिण्टर्स**, एस-1/208 के-1, नई बस्ती, पाण्डेयपुर, सारनाथ रोड, वाराणसी-221002